



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, अक्टूबर 20—अक्टूबर 26, 2019, शनिवार/आश्विन 28—कार्तिक 4, 1941
No. 43] NEW DELHI, OCTOBER 20—OCTOBER 26, 2019, SATURDAY/ASVINA 28—KARTIKA—4, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1866.—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार, गृह विभाग, भोपाल की अधिसूचना सं. एफ.12-85/2018/बी-1/2 दिनांक 19.9.2018 तथा सं. एफ.12-85/2018/बी-1/2 दिनांक 11.9.2019 के द्वारा जारी शुद्धिपत्र के माध्यम से प्राप्त सहमति से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, कटनी (मध्य प्रदेश) में भू अर्जन अधिकारी, बर्गी परियोजना, कटनी के नाम से धारित सरकारी खाते में रु. 4,09,84,470/- की गई धोखाधड़ी के मामले के सम्बन्ध में पुलिस थाना, माधव नगर, जिला-कटनी (मध्य प्रदेश) में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत पंजीकृत अपराध मामला सं. 1020/2017 तथा उपर्युक्त एक या अधिक अपराधों के संबंध में किए गए दुष्प्रयासों, दुष्प्रेरणाओं और षड्यंत्रों तथा उसी संव्यवहार में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध या अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त मध्य प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/54/2018-एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 18th October, 2019

S.O. 1866.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Madhya Pradesh, Home Department, Bhopal issued vide Notification No. F 12-85/2018/B-1/Two dated 19.9.2018 and its corrigendum issued vide No. F 12-85/2018/B-1/Two dated 11.9.2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in whole State of Madhya Pradesh for investigation of Criminal Case No. 1020/2017 under sections 406, 419, 420, 467, 468, 471 IPC registered at Police Station Madhav Nagar, Dist. Katni (M.P) in connection with an incident of fraud of Rs. 4,09,84,470 /- from the Government account standing in the name of the Land Acquisition Officer, Bargi Project, Katni at Central Bank of India, Main Branch, Katni (M.P) and any attempt, abetment and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offence(s) mentioned above and any other offence(s) committed in the course of same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/54/2018-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

का. आ. 1867.—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य सरकार, गृह विभाग, इम्फाल की अधिसूचना संख्या 12/1(4)/2018-एच(सीबीआई)(बैंक/गारंटी) दिनांक 10 जनवरी 2019, के माध्यम से प्राप्त सहमति से मैसर्स वुडहिल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल), भारत सरकार का उपक्रम से तामिनूलोंग-खोरांग रोड की अस्थायी मरम्मत हेतु ठेके का कार्य लेने के लिए 66.20 लाख रु. की कूटरचित बैंक गारंटी के प्रयोग के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 468, 471, 477-ए, 120-बी के अधीन सिटी पुलिस थाना की प्राथमिकी सं. 56(4)2016 के अधीन दर्ज मामले में अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त मणिपुर राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/07/2019-एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2019

S.O. 1867.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Manipur, Home Department, Imphal issued vide Notification No. 12/1(4)/2018-H(CBI)(Bank/Guarantee) dated 10th January 2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the Members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the State of Manipur for carrying out investigation into Case under FIR No. 56(4)2016 of City Police Station under sections 468, 471, 477-A, 120-B of Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) in connection with use of forged Bank Guarantee of Rs. 66.20 lakh for taking contract work for temporary restoration of Tamenglong-Khongang Road from National Highways & Infrastructure Development Corporation (NHIDCL), a Government of India Undertaking, by M/S Woodhill infrastructure Ltd.

[F. No. 228/07/2019 –AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

का. आ. 1868.—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य सरकार, गृह विभाग, इम्फाल की अधिसूचना संख्या 12/1(4)/2019-एच(सीबीआई)(सीडी) दिनांक 4 अप्रैल 2019, के माध्यम से प्राप्त सहमति से येरीपोक निगटथूनई, पुलिस थाना- आंद्रो, इम्फाल पूर्वी जिला के मोहम्मद मंजूर अहमद पुत्र स्वर्गीय एम.वी. बशीर अहमद की हिरासत में मौत के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 304 के अधीन इम्फाल पुलिस थाना की प्राथमिकी सं. 82(4)2019 के अधीन दर्ज मामले में अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त मणिपुर राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/10/2019-एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2019

S.O. 1868.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Manipur, Home Department, Imphal issued vide Notification No. 12/1(4)/2019-H(CBI)(CD) dated 4th April 2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the Members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the State of Manipur for carrying out investigation into Case under FIR No. 82(4)2019 of Imphal Police Station under section 304 of Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) in connection with custodial death of Md. Manjur Ahamad S/o (L) MV. Bashir Ahamad of Yairipok Ningthounai, PS-Andro, Imphal East District.

[F. No. 228/10/2019 –AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

का. आ. 1869.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम सं. 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग-3 के पत्र सं. 1770(2)पी/VI-पी-3-2018-15(06)पी/2018 लखनऊ, दिनांक 26.07.2018 के माध्यम से प्राप्त सहमति से भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 49) की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13(1)सी, 13(1)डी के अंतर्गत पुलिस थाना कासना, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में दर्ज अपराध सं. 421/2018 में आगे की जांच करने तथा उपर्युक्त एक या अधिक अपराधों के संबंध में किए गए किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र तथा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/35/2018-एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th October, 2019

S.O. 1869.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh Home (Police) Section-3 Letter No. 1770(2)P/VI-P-3-2018-15(06)P/2018 Lucknow dated 26.07.2018 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in whole State of Uttar Pradesh for further investigation of Crime No. 421/2018 under section 420, 467, 468, 471, 120-B of the Indian Penal Code and Section 13(1)(c), 13(1)(d) r/w 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49

of 1988) registered at Police Station, Kasna, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned above and any other offence (s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/35/2018 –AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 1870.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 766, तारीख 15 मई, 2019 के प्रकाशन पर, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख

18 मई, 2019 में प्रकाशित उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निम्मित अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि 71.77 हेक्टर या 177.43 एकड़ माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 18 मई, 2019 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

- (1) सरकारी कंपनी उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों आदि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;
- (2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और उक्त अधिकरण और किसी ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी व्यय भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ।

- (4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त भूमि और भूमि में या उसके उपर इस प्रकारनिहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[फा. सं. 43015/25/2016-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 23rd October, 2019

S. O. 1870.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 766, dated the 15th May, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th May, 2019, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, Nagpur, Maharashtra (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 71.77 hectares or 177.34 acres and all rights in or over the said land so vested, shall with effect from the 18th May, 2019 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company;
- (3) the Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
- (4) the Government Company shall have no power to transfer the lands to any other persons without the prior approval of the Central Government ; and
- (5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/25/2016-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1871.—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से ऊपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री वी. वेंकटेशु, सक्षम प्राधिकारी (आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, चौथी मंजिल, एल.आई.सी. एनेक्सी भवन, थिक्कना (डायमंड पार्क) रोड, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स के पास, विशाखापटनम – 530004, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : विशाखापटनम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
यलामंचिलि	एटिकोप्पाका	279/11	00	00	41
सब्बावरम	नारापाडु	177	00	05	07
		137/21	00	00	64

[फा. सं. आर-11025(11)252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. 1871.—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. B.Venkatesu, Competent Authority (Andhra Pradesh) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, 4th floor, LIC Annexe Building, Thikkana (Diamond Park) Road, Near RTC Complex, Visakhapatnam - 530004 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE					
DISTRICT : VISAKHAPATNAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
YELAMANCHILLI	ETIKOPPAKA	279/11	00	00	41
SABBAVARAM	NAARAPADU	177	00	05	07
		137/21	00	00	64

[F. No. R-11025(11)252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1872.—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से ऊपारब्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री बी. वेंकटेशु, सक्षम प्राधिकारी (आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, चौथी मंजिल, एल.आई.सी. एनेक्सी भवन, थिक्कना (डायमंड पार्क) रोड, आर.टी.सी. कॉम्पलेक्स के पास, विशाखापटनम - 530004, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : श्रीकाकुलम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोटाबोम्मालि	कुरुडु	512/7	0	0	66
		512/4F	0	0	97
		512/4D	0	0	34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		512/3B	0	1	77
		508/10	0	2	58
		508/16A	0	4	76
		508/9B	0	0	80
		507/5B	0	3	12
		507/3B	0	2	74
		507/3C	0	3	75
		507/3A	0	1	83
		438/8B	0	3	28
		438/6	0	0	3
		438/10	0	1	32
		438/11	0	1	8
		438/12	0	0	56
		439/3A	0	0	92
		439/3B	0	1	53
		439/5	0	2	67
		439/8	0	1	39
		439/9	0	0	56
		439/10	0	2	94
		433/11	0	0	42
		433/12	0	0	59
		433/10	0	0	58
		431/8	0	0	15
		401/8	0	0	25
		400/7	0	1	71
		399/7	0	0	96
		399/5	0	0	57
		399/3	0	1	64
		348/3	0	4	51
		353/8	0	2	87
		353/15	0	3	87
		353/11	0	2	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		355/2	0	2	1
		355/1	0	2	97
		357/8	0	0	97
		357/4	0	0	51
		357/7	0	2	74
		357/6	0	3	14
		357/5	0	3	14
		379/14	0	2	3
		379/15	0	3	95
		379/16	0	3	34
		379/10	0	0	51
		379/17	0	0	71
		379/9	0	0	71
		380/11	0	0	51
		380/12	0	12	45
		383/8	0	1	9
		383/7	0	1	82
		382/13	0	2	81
		382/12	0	0	82
		380/10	0	4	77
		512/18C	0	0	81
		512/18B	0	0	61
		512/18A	0	0	61
		508/14D	0	0	41
		508/14A	0	0	21
		508/9D	0	5	27
		507/2	0	1	62
		353/13P	0	0	81
		353/5	0	0	71
		353/9P	0	1	2
		358/9	0	0	41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोटाबोम्मालि	पाकिवलासा	23/5B	0	1	92
		23/3A	0	1	27
		23/3B	0	1	54
		23/13	0	3	14
		21/10	0	1	28
		21/9C	0	0	31
		21/5	0	0	26
		21/7	0	1	60
		41/4	0	2	86
		41/1	0	0	85
		42/17	0	0	26
		43/3A	0	0	4
		43/1	0	0	30
		43/2	0	1	62
		43/8	0	1	12
		49/1	0	2	53
		49/6	0	0	78
		49/8	0	0	61
		50/6	0	0	24
		50/7	0	2	99
		59/7	0	0	23
		59/4	0	2	44
		60/1	0	0	55
		60/5	0	0	82
		60/4	0	0	71
		61/1B	0	0	11
		61/7	0	0	21
		61/11B	0	1	60
		61/11C	0	0	1
		23/5C	0	0	81
		59/2	0	0	92
		59/6	0	1	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		61/1A	0	0	21
कोटाबोम्मालि	मासाहेबपेटा	120/1	0	1	42
		120/3	0	2	2
		116/1	0	2	2
		116/2	0	0	62
		116/6	0	10	90
		113/4	0	0	54
		113/8	0	0	67
		113/9	0	1	60
		113/11	0	0	32
		113/12	0	0	72
		114/1	0	0	18
		160/4	0	9	57
		160/10	0	0	56
		154/11	0	0	37
		154/10	0	0	4
		154/13	0	0	94
		154/22	0	0	38
		154/17	0	0	8
		154/16	0	0	11
		154/15	0	0	6
		154/19	0	0	31
		155/13	0	0	5
		151/20C	0	0	11
		151/16	0	1	95
		151/12	0	0	62
		151/14	0	0	81
		151/6	0	0	34
		150/2A	0	0	98
		150/2B	0	0	85
		151/21P	0	0	41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोटाबोम्मालि	पट्टपुरम	181/15	0	1	86
		181/12	0	2	48
		181/13	0	0	27
		182/23	0	0	84
		182/18	0	0	3
		182/19	0	0	67
		474/7	0	0	15
		474/2	0	1	50
		474/1	0	0	95
		209/4	0	2	62
		473/4	0	1	42
		473/8	0	1	10
		473/9	0	0	71
		225/9	0	0	29
		225/3	0	0	98
		223/14	0	0	69
		223/13	0	0	47
		223/9	0	0	35
		223/12	0	0	35
		223/4	0	1	18
		222/1	0	0	18
		345	0	3	3
		344/13	0	2	7
		343/12	0	3	8
		341/12	0	1	32
		341/15	0	0	8
		350/3	0	5	96
		350/2	0	4	69
		352/5	0	1	54
		352/6	0	0	52
		352/15	0	1	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		352/17	0	0	80
		352/19	0	1	33
		352/23	0	1	73
		352/22	0	0	20
		352/30	0	1	3
		352/32	0	1	74
		352/33	0	0	74
		352/34	0	0	71
		353/2	0	2	16
		353/8	0	0	1
		353/6	0	1	2
		353/13	0	0	2
		353/15	0	1	5
		353/17	0	0	14
		353/18	0	0	1
		354/11	0	1	7
		354/17	0	2	94
		403/11	0	0	92
		401/8	0	0	1
		404/7	0	2	25
		406	0	3	3
		437/7	0	4	5
		224/4	0	3	24
		354/15	0	0	41
		350/6	0	0	11
		342/14	0	0	21
		353/5	0	0	92
		353/3	0	0	51
		154/7	0	0	11
		343/11P	0	1	52
		154/2	0	2	23
		353/13	0	3	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		153/9	0	0	41
		353/1	0	0	11
		401/5	0	22	6
कोटाबोम्मालि	विश्वानाथापुरम	45/1	0	1	17
		45/5A	0	3	40
		41/10A	0	0	28
		41/10B	0	2	42
		41/7	0	0	30
		39/4	0	0	95
		39/8	0	0	6
		39/7	0	1	60
		35/2	0	0	15
		35/18	0	0	10
		20/17	0	0	84
		21/3A	0	0	91
		22/7	0	0	37
		22/16J	0	1	18
		23/10	0	0	6
		23/1	0	1	12
		12/20	0	0	51
		12/15	0	0	34
		13/2	0	2	66
		13/4	0	0	10
		20/19	0	4	46
		19	0	0	61
		20/16	0	2	74
		39/5	0	2	3
		22/8	0	2	84
		22/1	0	1	62
		22/11	0	0	61
		13/21A	0	0	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13/21B	0	2	43
		22/13A	0	1	2
		22/13B	0	0	81
		20/21	0	3	95
		41/9	0	0	11
		22/11	0	0	21
जलमूर	तलातरिया	382/14	0	0	71
		382/15P	0	0	43
		382/13	0	1	14
		383/2	0	0	39
		383/5	0	0	8
		383/7	0	3	46
		385/9	0	0	11
		358/10	0	0	99
		385/1	0	0	51
		389/1	0	1	30
		387/4	0	1	52
		387/5	0	0	85
		387/6	0	0	3
		347/1	0	6	6
		347/2	0	1	75
		343/3	0	0	9
		343/7	0	0	3
		343/8	0	0	5
		343/1	0	3	6
		333/22	0	0	66
		333/11	0	0	66
		333/10	0	1	7
		333/12	0	0	13
		333/6	0	0	91
		333/5	0	0	67

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		335/18	0	0	99
		335/21	0	0	47
		335/20	0	0	19
		335/14	0	0	15
		337/11	0	0	58
		335/11	0	0	66
		335/9	0	0	13
		336/2	0	1	55
		336/5	0	0	11
		336/1	0	1	71
		336/7	0	0	31
		392/2	0	2	84
		345/3	0	1	72
		345/6	0	6	88
		345/5	0	4	5
		346/2	0	12	35
कोटाबोम्मालि	आनंदापुरम	139/6	0	0	5
		140/1	0	3	64
		141/2	0	7	69
		142/1A	0	2	60
		128/9	0	1	40
		127/1	0	5	68
		127/3	0	2	4
		142/4	0	0	21
कोटाबोम्मालि	सौडाम	119	0	4	21
		118	0	0	51
जलुमूरु	दरिवाड़ा	67/7	0	3	54
		113/8	0	2	94
		113/9	0	2	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		111/4	0	3	5
		110/14	0	0	4
		109/7D	0	1	10
		108/9	0	1	2
		107/6P	0	1	2
		107/5	0	0	66
		107/7E	0	0	11
		115/4	0	10	12
जलुमूरु	लिंगालावलासा	190/2	0	0	21
		187/9	0	0	60
		187/14	0	0	3
		187/13	0	0	8
		187/12	0	0	27
		179/7	0	9	26
		178/3	0	2	92
		197/2	0	0	88
		197/10	0	0	32
		178/17	0	1	67
		199/1	0	1	96
		200/3P	0	0	51
		200/5	0	0	41
		200/7	0	0	66
		200/10	0	0	35
		200/9	0	0	15
		354/6	0	0	70
		354/7	0	0	33
		354/8B	0	0	23
		354/8A	0	3	8
		354/10	0	0	6
		354/11A	0	1	32
		353/3A	0	0	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		353/2	0	0	54
		350/1	0	0	7
		352/4	0	0	92
		351/7	0	1	44
		349/3	0	0	11
		187/18	0	0	11
		178/1	0	0	61
जलुमूर	राणा	174/4	0	2	51
		174/3	0	1	74
		174/2	0	5	79
		174/8	0	0	39
		173/1	0	1	12
		169/4	0	0	25
		170/8	0	0	10
		170/7	0	0	29
		170/3	0	1	15
		165/8P	0	2	79
		165/2	0	0	42
		165/1	0	2	1
		165/3	0	0	52
		165/4	0	0	54
		157/20	0	2	63
		157/19	0	3	87
		157/6	0	1	54
		156/2	0	4	10
		156/1	0	0	45
		156/4	0	4	7
		156/5	0	7	39
		149/22	0	1	8
		149/23	0	2	21
		149/27	0	8	63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		150/5	0	0	9
		150/4	0	0	13
		150/3	0	2	33
		150/2	0	2	28
		137/12	0	3	6
		137/10	0	1	19
		137/9	0	1	47
		137/2	0	0	94
		137/1	0	0	99
		138/4	0	0	37
		138/2	0	3	18
		138/7	0	2	49
		130/1	0	1	43
		130/4	0	6	51
		131/3	0	0	3
		128/15	0	0	65
		156/12	0	0	61
		156/6	0	0	11
		150/9	0	0	41
		150/6	0	3	4
		150/8	0	0	51
जलमूर	पेदादूगाम	76/26	0	2	11
		81/12C	0	2	70
		89/1	0	2	39
		85/2	0	2	73
		88	0	0	2
		141/11	0	1	56
		141/8	0	1	20
		142/2	0	0	2
		142/8	0	0	2
		144/12	0	1	58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		145/10	0	0	77
		145/11	0	0	41
		145/12	0	0	8
		145/13	0	4	49
		81/11	0	8	40
		79/8	0	2	84
		81/9	0	3	65
		79/7	0	1	72
जलुमूर	चिन्नादूगाम	17/1	0	0	81
		18/7	0	0	8
		18/6	0	0	26
		18/1	0	0	51
		27/2	0	3	34
		27/4	0	6	48
		25/1	0	7	80
जलुमूर	बसिवाड़ा	146/3	0	1	36
		146/4	0	0	60
		145/4	0	6	24
		145/5	0	1	13
		145/7	0	0	84
		142/6	0	0	67
		142/10A	0	2	56
		111/1	0	0	82
		110/2	0	0	36
		107/2	0	0	19
		149/7	0	3	24
कविटि	कारापाडु	28/2	0	9	13
		20/12	0	1	0
		20/13	0	0	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		20/6	0	0	73
		30/17	0	1	8
		31/15	0	3	38
		33/5	0	2	11
		32/10	0	2	34
		46/3	0	1	12
		46/13	0	0	11
		46/19	0	0	91
		52/5	0	0	30
		52/12	0	0	4
		52/15	0	0	60
		52/18	0	0	17
		54/2	0	0	47
		55/2	0	0	44
		55/9	0	2	92
		91/8	0	1	87
		31/9	0	1	14
		31/10	0	0	46
		33/4	0	4	76
		34/6	0	0	57
		46/8	0	0	21
		46/14	0	0	50
		46/20	0	0	32
		46/27	0	0	44
		52/11	0	0	68
		46/18P	0	0	92
		57/1	0	0	11
		30/13	0	10	93
		55/13	0	0	11
कविटि	सिलागाम	15/1	0	3	54
		5	0	0	46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14/2	0	4	25
		13/2	0	1	62
कविटि	बेलागाम	44/12	0	0	25
		44/10	0	1	17
		44/14	0	1	20
		44/16	0	2	11
		44/19	0	0	73
		59/3	0	2	20
		59/13	0	4	35
		60/11	0	0	52
		60/4	0	0	40
		60/2	0	0	1
		170/2	0	0	31
		170/3	0	0	1
		170/6	0	0	5
		170/7	0	0	11
		170/8	0	0	55
		170/21	0	1	57
		171/24	0	0	20
		171/20	0	2	0
		172/1	0	2	40
		174/1	0	1	71
		174/4	0	1	38
		191/4	0	2	3
		191/3	0	0	7
		191/2	0	2	24
		191/10	0	0	41
		193/13	0	0	21
		193/12	0	0	13
		193/11	0	0	89
		193/10	0	0	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		192/2	0	0	49
		192/3	0	0	38
		192/4	0	0	20
		209/3	0	0	7
		209/6	0	0	8
		209/7	0	0	25
		209/14	0	0	15
		208/1	0	0	91
		208/2	0	0	27
		208/3	0	0	1
		208/5	0	0	36
		208/7	0	0	40
		208/8	0	0	52
		208/10	0	0	24
		208/11	0	0	5
		45	0	2	75
		60/8	0	0	30
		60/3	0	0	88
		170/1	0	2	10
		171/12	0	0	82
		171/11	0	2	48
		173/6	0	0	58
		173/4	0	1	29
		193/3	0	2	8
		192/1	0	0	1
		43/6	0	0	42
		36/10	0	0	29
		35/11	0	1	35
		32/14	0	0	57
		43/7	0	0	83
		35/17	0	1	28
		35/14	0	1	85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		37/1	0	0	59
		35/9	0	5	27
		32/20	0	1	40
		32/19	0	1	50
		170/18B	0	5	67
		59/12	0	0	11
		171/10	0	0	41
		173/13	0	2	23
		172/5	0	0	41
		173/12	0	0	41
		32/24	0	0	41
		33/2	0	2	64
		209/12	0	1	72
		174/2	0	1	52
		173/12	0	1	72
		171/19	0	0	71
		44/13	0	3	85
कंचिलि	जाडुपूडि	14/14	0	0	43
		14/13	0	0	92
		14/5	0	2	87
		15/5	0	0	3
		16/2	0	0	45
		16/1	0	0	78
		16/25	0	0	13
		12/17	0	0	61
		45/14	0	0	59
		45/15	0	0	43
		45/18	0	0	13
		45/17	0	0	2
		45/19	0	0	14
		45/20	0	0	46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		45/24	0	0	17
		52/18	0	0	31
		52/19	0	1	11
		51/8	0	0	12
		51/9	0	0	23
		60/10	0	0	33
		60/17	0	0	97
		60/15	0	1	34
		61/1	0	0	46
		61/5	0	0	18
		61/6	0	0	16
		62/3	0	0	12
		62/4	0	0	71
		294/4	0	1	18
		294/6	0	0	1
		301/17	0	0	29
		301/9	0	0	44
		301/8	0	0	7
		307/6	0	0	8
		307/7	0	1	12
		306/5	0	0	77
		315/1	0	0	70
		315/2	0	2	44
		15/2	0	0	21
		42/22	0	0	21
		14/10	0	0	21
		14/4	0	0	11
		52/2	0	0	11
		15/1	0	0	21
		45/8	0	0	11
		52/15	0	0	92
		15/3	0	0	81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		295/4	0	4	76
		14/3	0	1	52
कंचिलि	बिन्नला कोत्तूर	334/8	0	0	24
		334/4	0	0	32
		334/3	0	0	2
		334/5	0	0	7
		334/6	0	0	17
		331/3	0	0	95
		331/5	0	1	62
		330/1	0	1	73
		331/11	0	2	3
कंचिलि	कीसरिपाड़ा	484	0	1	85
		482/15	0	1	32
		483/3	0	1	33
		496/1	0	0	11
		496/2	0	0	68
		496/4	0	0	46
		496/5	0	0	31
		497/16	0	0	73
		498/1	0	2	49
		503/1	0	0	66
		504/17	0	0	17
		504/18	0	2	15
		504/14	0	0	85
		504/11	0	0	62
		504/12	0	0	34
		504/13	0	1	63
		506/14	0	0	73
		506/13	0	1	51
		519/4	0	0	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		518/8	0	0	71
		518/5	0	0	58
		531/1	0	0	9
		532/9	0	2	96
		533/11	0	0	85
		533/9	0	1	14
		534/16	0	0	27
		534/15	0	1	68
		534/14	0	0	87
		535/10	0	1	15
		535/3	0	0	56
		483/11	0	0	31
		483/8	0	0	11
		518/7	0	0	11
		403/10	0	1	83
		533/12	0	0	21
कंचिलि	जलंघाकोटा	138/3	0	1	42
		137/3	0	3	83
		149/10	0	0	66
		149/2	0	6	63
		160/2	0	2	11
		160/4	0	0	39
		160/5	0	0	7
		165	0	13	80
		163/3	0	0	17
		164	0	6	21
		172	0	6	33
		138/2	0	2	94
		173/2	0	0	11
		131/1	0	7	49
		149/P	0	1	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कंचिलि	जेन्नागाया	30/6	0	1	49
		30/4	0	0	15
		30/18	0	1	30
		31/5	0	1	5
		34/4	0	0	64
		31/6	0	1	15
		34/10	0	0	51
		33/11	0	0	3
		32/1	0	0	41
		32/6	0	0	87
		32/7	0	1	31
		33/17	0	0	24
		65	0	8	69
		64/3	0	0	15
		64/2	0	2	66
		64/1	0	1	90
		63/3	0	0	84
		63/1	0	1	59
		54/2	0	1	0
		54/4	0	0	30
		54/3	0	0	28
		56/2	0	0	93
		53/4	0	0	31
		32/5	0	0	21
कंचिलि	गोकर्नापुरम	42/8	0	0	21
		41/1	0	0	59
		41/5	0	0	79
		44/1	0	0	37
		44/10	0	0	31
		51/8	0	1	47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		51/7	0	0	62
		50/7	0	0	70
		49/8	0	2	96
		49/10	0	0	45
		71/18	0	0	34
		71/19	0	2	19
		44/8	0	6	99
		44/11	0	4	5
		44/9	0	4	46
		114/1	0	0	7
		109/1A	0	0	25
		107/4	0	2	64
		107/7A	0	0	74
		348/5B	0	0	3
		346/6d	0	3	13
		346/6A	0	1	2
		346/8	0	0	7
		109/10	0	1	62
		346/14	0	1	93
कंचिलि	शासनाम	365/2	0	1	92
		371	0	19	29
		379/2B	0	1	8
		386	0	6	25
		374/4	0	11	74
संताबोम्मालि	बृंदावनम	36/6	00	01	62
इच्छापुरम	मंडापल्लि	237/8	00	01	62
		116/1	00	04	45
		210/13	00	02	75
		176/12	00	01	52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नंदिगाम	कोमाटूर	164/8	00	00	10
नंदिगाम	लट्टिगाम	21/1	00	02	83
		32/9	00	00	24
		30/3B	00	00	89
		39/1	00	00	28
		39/3	00	01	05
नंदिगाम	संतोषापुरम	41/7	00	02	41
नंदिगाम	कोंडातेबूरु	67/7	00	01	13
		67/3	00	01	05
		66/11	00	00	13
		61/8	00	00	69
नंदिगाम	कोत्ताअग्रहारम	40/4	00	02	94
		59/5	00	00	71
		58/10	00	00	20
		39/8	00	01	72
पलासा	कोयुजोला	297/10	00	00	81
पलासा	अडविकोत्तूरु	289/3	00	00	81
		228/2	00	00	40
पलासा	बंतुकोत्तूरु	210	00	02	15
वज्रापुकत्तूरु	उंडरुकुडिया	42/5	00	01	62
कविटि	कारापाडु	54/17	00	02	93
		20/11	00	02	02

[फा. सं. आर-11025(11)252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. 1872.—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. B. Venkatesu, Competent Authority (Andhra Pradesh) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, 4th floor, LIC Annexe Building, Thikkana (Diamond Park) Road, Near RTC Complex, Visakhapatnam - 530004 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

DISTRICT : SRIKAKULAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KOTABOMMALI	KURUDU	512/7	0	0	66
		512/4F	0	0	97
		512/4D	0	0	34
		512/3B	0	1	77
		508/10	0	2	58
		508/16A	0	4	76
		508/9B	0	0	80
		507/5B	0	3	12
		507/3B	0	2	74
		507/3C	0	3	75
		507/3A	0	1	83
		438/8B	0	3	28
		438/6	0	0	3
		438/10	0	1	32
		438/11	0	1	8
		438/12	0	0	56
		439/3A	0	0	92
		439/3B	0	1	53
		439/5	0	2	67
		439/8	0	1	39
		439/9	0	0	56
		439/10	0	2	94
		433/11	0	0	42
		433/12	0	0	59
		433/10	0	0	58
		431/8	0	0	15
		401/8	0	0	25
		400/7	0	1	71
		399/7	0	0	96

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		399/5	0	0	57
		399/3	0	1	64
		348/3	0	4	51
		353/8	0	2	87
		353/15	0	3	87
		353/11	0	2	33
		355/2	0	2	1
		355/1	0	2	97
		357/8	0	0	97
		357/4	0	0	51
		357/7	0	2	74
		357/6	0	3	14
		357/5	0	3	14
		379/14	0	2	3
		379/15	0	3	95
		379/16	0	3	34
		379/10	0	0	51
		379/17	0	0	71
		379/9	0	0	71
		380/11	0	0	51
		380/12	0	12	45
		383/8	0	1	9
		383/7	0	1	82
		382/13	0	2	81
		382/12	0	0	82
		380/10	0	4	77
		512/18C	0	0	81
		512/18B	0	0	61
		512/18A	0	0	61
		508/14D	0	0	41
		508/14A	0	0	21
		508/9D	0	5	27
		507/2	0	1	62
		353/13P	0	0	81
		353/5	0	0	71
		353/9P	0	1	2
		358/9	0	0	41
KOTABOMMALI	PAKIVALASA	23/5B	0	1	92
		23/3A	0	1	27
		23/3B	0	1	54
		23/13	0	3	14
		21/10	0	1	28
		21/9C	0	0	31
		21/5	0	0	26
		21/7	0	1	60
		41/4	0	2	86
		41/1	0	0	85
		42/17	0	0	26
		43/3A	0	0	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		43/1	0	0	30
		43/2	0	1	62
		43/8	0	1	12
		49/1	0	2	53
		49/6	0	0	78
		49/8	0	0	61
		50/6	0	0	24
		50/7	0	2	99
		59/7	0	0	23
		59/4	0	2	44
		60/1	0	0	55
		60/5	0	0	82
		60/4	0	0	71
		61/1B	0	0	11
		61/7	0	0	21
		61/11B	0	1	60
		61/11C	0	0	1
		23/5C	0	0	81
		59/2	0	0	92
		59/6	0	1	22
		61/1A	0	0	21
KOTABOMMALI	MASAHABPETA	120/1	0	1	42
		120/3	0	2	2
		116/1	0	2	2
		116/2	0	0	62
		116/6	0	10	90
		113/4	0	0	54
		113/8	0	0	67
		113/9	0	1	60
		113/11	0	0	32
		113/12	0	0	72
		114/1	0	0	18
		160/4	0	9	57
		160/10	0	0	56
		154/11	0	0	37
		154/10	0	0	4
		154/13	0	0	94
		154/22	0	0	38
		154/17	0	0	8
		154/16	0	0	11
		154/15	0	0	6
		154/19	0	0	31
		155/13	0	0	5
		151/20C	0	0	11
		151/16	0	1	95
		151/12	0	0	62
		151/14	0	0	81
		151/6	0	0	34
		150/2A	0	0	98

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		150/2B	0	0	85
		151/21P	0	0	41
KOTABOMMALI	PATTUPURAM	181/15	0	1	86
		181/12	0	2	48
		181/13	0	0	27
		182/23	0	0	84
		182/18	0	0	3
		182/19	0	0	67
		474/7	0	0	15
		474/2	0	1	50
		474/1	0	0	95
		209/4	0	2	62
		473/4	0	1	42
		473/8	0	1	10
		473/9	0	0	71
		225/9	0	0	29
		225/3	0	0	98
		223/14	0	0	69
		223/13	0	0	47
		223/9	0	0	35
		223/12	0	0	35
		223/4	0	1	18
		222/1	0	0	18
		345	0	3	3
		344/13	0	2	7
		343/12	0	3	8
		341/12	0	1	32
		341/15	0	0	8
		350/3	0	5	96
		350/2	0	4	69
		352/5	0	1	54
		352/6	0	0	52
		352/15	0	1	54
		352/17	0	0	80
		352/19	0	1	33
		352/23	0	1	73
		352/22	0	0	20
		352/30	0	1	3
		352/32	0	1	74
		352/33	0	0	74
		352/34	0	0	71
		353/2	0	2	16
		353/8	0	0	1
		353/6	0	1	2
		353/13	0	0	2
		353/15	0	1	5
		353/17	0	0	14
		353/18	0	0	1
		354/11	0	1	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		354/17	0	2	94
		403/11	0	0	92
		401/8	0	0	1
		404/7	0	2	25
		406	0	3	3
		437/7	0	4	5
		224/4	0	3	24
		354/15	0	0	41
		350/6	0	0	11
		342/14	0	0	21
		353/5	0	0	92
		353/3	0	0	51
		154/7	0	0	11
		343/11P	0	1	52
		154/2	0	2	23
		353/13	0	3	24
		153/9	0	0	41
		353/1	0	0	11
		401/5	0	22	6
KOTABOMMALI	VISWANADHAPURAM	45/1	0	1	17
		45/5A	0	3	40
		41/10A	0	0	28
		41/10B	0	2	42
		41/7	0	0	30
		39/4	0	0	95
		39/8	0	0	6
		39/7	0	1	60
		35/2	0	0	15
		35/18	0	0	10
		20/17	0	0	84
		21/3A	0	0	91
		22/7	0	0	37
		22/16J	0	1	18
		23/10	0	0	6
		23/1	0	1	12
		12/20	0	0	51
		12/15	0	0	34
		13/2	0	2	66
		13/4	0	0	10
		20/19	0	4	46
		19	0	0	61
		20/16	0	2	74
		39/5	0	2	3
		22/8	0	2	84
		22/1	0	1	62
		22/11	0	0	61
		13/21A	0	0	21
		13/21B	0	2	43
		22/13A	0	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		22/13B	0	0	81
		20/21	0	3	95
		41/9	0	0	11
		22/11	0	0	21
JALUMURU	TALATARIA	382/14	0	0	71
		382/15P	0	0	43
		382/13	0	1	14
		383/2	0	0	39
		383/5	0	0	8
		383/7	0	3	46
		385/9	0	0	11
		358/10	0	0	99
		385/1	0	0	51
		389/1	0	1	30
		387/4	0	1	52
		387/5	0	0	85
		387/6	0	0	3
		347/1	0	6	6
		347/2	0	1	75
		343/3	0	0	9
		343/7	0	0	3
		343/8	0	0	5
		343/1	0	3	6
		333/22	0	0	66
		333/11	0	0	66
		333/10	0	1	7
		333/12	0	0	13
		333/6	0	0	91
		333/5	0	0	67
		335/18	0	0	99
		335/21	0	0	47
		335/20	0	0	19
		335/14	0	0	15
		337/11	0	0	58
		335/11	0	0	66
		335/9	0	0	13
		336/2	0	1	55
		336/5	0	0	11
		336/1	0	1	71
		336/7	0	0	31
		392/2	0	2	84
		345/3	0	1	72
		345/6	0	6	88
		345/5	0	4	5
		346/2	0	12	35
KOTABOMMALI	ANANDAPURAM	139/6	0	0	5
		140/1	0	3	64
		141/2	0	7	69

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		142/1A	0	2	60
		128/9	0	1	40
		127/1	0	5	68
		127/3	0	2	4
		142/4	0	0	21
KOTABOMMALI	SOUDAM	119	0	4	21
		118	0	0	51
JALUMURU	DARIVADA	67/7	0	3	54
		113/8	0	2	94
		113/9	0	2	30
		111/4	0	3	5
		110/14	0	0	4
		109/7D	0	1	10
		108/9	0	1	2
		107/6P	0	1	2
		107/5	0	0	66
		107/7E	0	0	11
		115/4	0	10	12
JALUMURU	LINGALAVALASA	190/2	0	0	21
		187/9	0	0	60
		187/14	0	0	3
		187/13	0	0	8
		187/12	0	0	27
		179/7	0	9	26
		178/3	0	2	92
		197/2	0	0	88
		197/10	0	0	32
		178/17	0	1	67
		199/1	0	1	96
		200/3P	0	0	51
		200/5	0	0	41
		200/7	0	0	66
		200/10	0	0	35
		200/9	0	0	15
		354/6	0	0	70
		354/7	0	0	33
		354/8B	0	0	23
		354/8A	0	3	8
		354/10	0	0	6
		354/11A	0	1	32
		353/3A	0	0	31
		353/2	0	0	54
		350/1	0	0	7
		352/4	0	0	92
		351/7	0	1	44
		349/3	0	0	11
		187/18	0	0	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		178/1	0	0	61
JALUMURU	RANA	174/4	0	2	51
		174/3	0	1	74
		174/2	0	5	79
		174/8	0	0	39
		173/1	0	1	12
		169/4	0	0	25
		170/8	0	0	10
		170/7	0	0	29
		170/3	0	1	15
		165/8P	0	2	79
		165/2	0	0	42
		165/1	0	2	1
		165/3	0	0	52
		165/4	0	0	54
		157/20	0	2	63
		157/19	0	3	87
		157/6	0	1	54
		156/2	0	4	10
		156/1	0	0	45
		156/4	0	4	7
		156/5	0	7	39
		149/22	0	1	8
		149/23	0	2	21
		149/27	0	8	63
		150/5	0	0	9
		150/4	0	0	13
		150/3	0	2	33
		150/2	0	2	28
		137/12	0	3	6
		137/10	0	1	19
		137/9	0	1	47
		137/2	0	0	94
		137/1	0	0	99
		138/4	0	0	37
		138/2	0	3	18
		138/7	0	2	49
		130/1	0	1	43
		130/4	0	6	51
		131/3	0	0	3
		128/15	0	0	65
		156/12	0	0	61
		156/6	0	0	11
		150/9	0	0	41
		150/6	0	3	4
		150/8	0	0	51
JALUMURU	PEDDADUGAM	76/26	0	2	11
		81/12C	0	2	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		89/1	0	2	39
		85/2	0	2	73
		88	0	0	2
		141/11	0	1	56
		141/8	0	1	20
		142/2	0	0	2
		142/8	0	0	2
		144/12	0	1	58
		145/10	0	0	77
		145/11	0	0	41
		145/12	0	0	8
		145/13	0	4	49
		81/11	0	8	40
		79/8	0	2	84
		81/9	0	3	65
		79/7	0	1	72
JALUMURU	CHINNA DUGAM	17/1	0	0	81
		18/7	0	0	8
		18/6	0	0	26
		18/1	0	0	51
		27/2	0	3	34
		27/4	0	6	48
		25/1	0	7	80
JALUMURU	BASIVADA	146/3	0	1	36
		146/4	0	0	60
		145/4	0	6	24
		145/5	0	1	13
		145/7	0	0	84
		142/6	0	0	67
		142/10A	0	2	56
		111/1	0	0	82
		110/2	0	0	36
		107/2	0	0	19
		149/7	0	3	24
KAVITI	KARAPADU	28/2	0	9	13
		20/12	0	1	0
		20/13	0	0	12
		20/6	0	0	73
		30/17	0	1	8
		31/15	0	3	38
		33/5	0	2	11
		32/10	0	2	34
		46/3	0	1	12
		46/13	0	0	11
		46/19	0	0	91
		52/5	0	0	30
		52/12	0	0	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		52/15	0	0	60
		52/18	0	0	17
		54/2	0	0	47
		55/2	0	0	44
		55/9	0	2	92
		91/8	0	1	87
		31/9	0	1	14
		31/10	0	0	46
		33/4	0	4	76
		34/6	0	0	57
		46/8	0	0	21
		46/14	0	0	50
		46/20	0	0	32
		46/27	0	0	44
		52/11	0	0	68
		46/18P	0	0	92
		57/1	0	0	11
		30/13	0	10	93
		55/13	0	0	11
KAVITI	SILAGAM	15/1	0	3	54
		5	0	0	46
		14/2	0	4	25
		13/2	0	1	62
KAVITI	BELAGAUM	44/12	0	0	25
		44/10	0	1	17
		44/14	0	1	20
		44/16	0	2	11
		44/19	0	0	73
		59/3	0	2	20
		59/13	0	4	35
		60/11	0	0	52
		60/4	0	0	40
		60/2	0	0	1
		170/2	0	0	31
		170/3	0	0	1
		170/6	0	0	5
		170/7	0	0	11
		170/8	0	0	55
		170/21	0	1	57
		171/24	0	0	20
		171/20	0	2	0
		172/1	0	2	40
		174/1	0	1	71
		174/4	0	1	38
		191/4	0	2	3
		191/3	0	0	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		191/2	0	2	24
		191/10	0	0	41
		193/13	0	0	21
		193/12	0	0	13
		193/11	0	0	89
		193/10	0	0	50
		192/2	0	0	49
		192/3	0	0	38
		192/4	0	0	20
		209/3	0	0	7
		209/6	0	0	8
		209/7	0	0	25
		209/14	0	0	15
		208/1	0	0	91
		208/2	0	0	27
		208/3	0	0	1
		208/5	0	0	36
		208/7	0	0	40
		208/8	0	0	52
		208/10	0	0	24
		208/11	0	0	5
		45	0	2	75
		60/8	0	0	30
		60/3	0	0	88
		170/1	0	2	10
		171/12	0	0	82
		171/11	0	2	48
		173/6	0	0	58
		173/4	0	1	29
		193/3	0	2	8
		192/1	0	0	1
		43/6	0	0	42
		36/10	0	0	29
		35/11	0	1	35
		32/14	0	0	57
		43/7	0	0	83
		35/17	0	1	28
		35/14	0	1	85
		37/1	0	0	59
		35/9	0	5	27
		32/20	0	1	40
		32/19	0	1	50
		170/18B	0	5	67
		59/12	0	0	11
		171/10	0	0	41
		173/13	0	2	23
		172/5	0	0	41
		173/12	0	0	41
		32/24	0	0	41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		33/2	0	2	64
		209/12	0	1	72
		174/2	0	1	52
		173/12	0	1	72
		171/19	0	0	71
		44/13	0	3	85
KAVITI	JADUPUDI	14/14	0	0	43
		14/13	0	0	92
		14/5	0	2	87
		15/5	0	0	3
		16/2	0	0	45
		16/1	0	0	78
		16/25	0	0	13
		12/17	0	0	61
		45/14	0	0	59
		45/15	0	0	43
		45/18	0	0	13
		45/17	0	0	2
		45/19	0	0	14
		45/20	0	0	46
		45/24	0	0	17
		52/18	0	0	31
		52/19	0	1	11
		51/8	0	0	12
		51/9	0	0	23
		60/10	0	0	33
		60/17	0	0	97
		60/15	0	1	34
		61/1	0	0	46
		61/5	0	0	18
		61/6	0	0	16
		62/3	0	0	12
		62/4	0	0	71
		294/4	0	1	18
		294/6	0	0	1
		301/17	0	0	29
		301/9	0	0	44
		301/8	0	0	7
		307/6	0	0	8
		307/7	0	1	12
		306/5	0	0	77
		315/1	0	0	70
		315/2	0	2	44
		15/2	0	0	21
		42/22	0	0	21
		14/10	0	0	21
		14/4	0	0	11
		52/2	0	0	11
		15/1	0	0	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		45/8	0	0	11
		52/15	0	0	92
		15/3	0	0	81
		295/4	0	4	76
		14/3	0	1	52
KAVITI	BHINNALAKOTTURU	334/8	0	0	24
		334/4	0	0	32
		334/3	0	0	2
		334/5	0	0	7
		334/6	0	0	17
		331/3	0	0	95
		331/5	0	1	62
		330/1	0	1	73
		331/11	0	2	3
KANCHILI	KISARIPADA	484	0	1	85
		482/15	0	1	32
		483/3	0	1	33
		496/1	0	0	11
		496/2	0	0	68
		496/4	0	0	46
		496/5	0	0	31
		497/16	0	0	73
		498/1	0	2	49
		503/1	0	0	66
		504/17	0	0	17
		504/18	0	2	15
		504/14	0	0	85
		504/11	0	0	62
		504/12	0	0	34
		504/13	0	1	63
		506/14	0	0	73
		506/13	0	1	51
		519/4	0	0	13
		518/8	0	0	71
		518/5	0	0	58
		531/1	0	0	9
		532/9	0	2	96
		533/11	0	0	85
		533/9	0	1	14
		534/16	0	0	27
		534/15	0	1	68
		534/14	0	0	87
		535/10	0	1	15
		535/3	0	0	56
		483/11	0	0	31
		483/8	0	0	11
		518/7	0	0	11
		403/10	0	1	83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		533/12	0	0	21
KANCHILI	JALANTRAKOTA	138/3	0	1	42
		137/3	0	3	83
		149/10	0	0	66
		149/2	0	6	63
		160/2	0	2	11
		160/4	0	0	39
		160/5	0	0	7
		165	0	13	80
		163/3	0	0	17
		164	0	6	21
		172	0	6	33
		138/2	0	2	94
		173/2	0	0	11
		131/1	0	7	49
		149/P	0	1	42
KANCHILI	JENNAGAYA	30/6	0	1	49
		30/4	0	0	15
		30/18	0	1	30
		31/5	0	1	5
		34/4	0	0	64
		31/6	0	1	15
		34/10	0	0	51
		33/11	0	0	3
		32/1	0	0	41
		32/6	0	0	87
		32/7	0	1	31
		33/17	0	0	24
		65	0	8	69
		64/3	0	0	15
		64/2	0	2	66
		64/1	0	1	90
		63/3	0	0	84
		63/1	0	1	59
		54/2	0	1	0
		54/4	0	0	30
		54/3	0	0	28
		56/2	0	0	93
		53/4	0	0	31
		32/5	0	0	21
KANCHILI	GOKARNAPURAM	42/8	0	0	21
		41/1	0	0	59
		41/5	0	0	79
		44/1	0	0	37
		44/10	0	0	31
		51/8	0	1	47
		51/7	0	0	62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		50/7	0	0	70
		49/8	0	2	96
		49/10	0	0	45
		71/18	0	0	34
		71/19	0	2	19
		44/8	0	6	99
		44/11	0	4	5
		44/9	0	4	46
		114/1	0	0	7
		109/1A	0	0	25
		107/4	0	2	64
		107/7A	0	0	74
		348/5B	0	0	3
		346/6d	0	3	13
		346/6A	0	1	2
		346/8	0	0	7
		109/10	0	1	62
		346/14	0	1	93
KANCHILI	SASANAM	365/2	0	1	92
		371	0	19	29
		379/2B	0	1	8
		386	0	6	25
		374/4	0	11	74
SANTHA BOMMALI	BRUNDAVANAM	36/6	00	01	62
ICHCHAPURAM	MANDAPALLI	237/8	00	01	62
		116/1	00	04	45
		210/13	00	02	75
		176/12	00	01	52
NANDIGAM	KOMATURU	164/8	00	00	10
NANDIGAM	LATTIGAM	21/1	00	02	83
		32/9	00	00	24
		30/3B	00	00	89
		39/1	00	00	28
		39/3	00	01	05
NANDIGAM	SANTOSAPURAM	41/7	00	02	41
NANDIGAM	KONDA THEMBURU	67/7	00	01	13
		67/3	00	01	05
		66/11	00	00	13
		61/8	00	00	69
NANDIGAM	KOTTA AGRAHARAM	40/4	00	02	94
		59/5	00	00	71
		58/10	00	00	20
		39/8	00	01	72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PALASA	KOYUJOLA	297/10	00	00	81
PALASA	ADIVIKOTTURU	289/3	00	00	81
		228/2	00	00	40
PALASA	BANTU KOTTURU	210	00	02	15
VAJRAPUKATHURU	UNDRUKUDIYA	42/5	00	01	62
KAVITI	KARAPADU	54/17	00	02	93
		20/11	00	02	02

[F. No. R-11025(11)252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1873.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडू राज्य के सेलम को केरल राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए, एक पाइपलाईन कोच्चि सेलम पाइपलाईन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिये उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री बशीरकुंजू ए, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइप लाइन प्राइवेट लिमिटेड, करुण एंक्लेव, द्वितीय तल, डोर नं. बी- 2, एस एन जंक्शन, रिफाइनरी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने, त्रिपुनिथुरा, जिला ऐरनाकुलम, केरल — 682301 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

राज्य: केरल

जिला: त्रिशूर

तालुक: त्रिशूर

नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
मारतक्करा (खण्ड सं. 72)	108 / 5	0	01	40
	108 / 20	0	00	60

राज्य: केरल

जिला: ऐरनाकुलम

तालुक: आलुवा

नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
तेक्कुम्बागम (खण्ड सं. 30)	239 / 5	0	01	00

[फा. सं. आर-12031 / 196 / 2017-ओआर-I/ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. 1873.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/S Kochi – Salem pipeline Private Ltd;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule annexed to this notification;

Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to Sri. Basheerkunju. A, Competent Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd, Karun Enclave 2nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road, Tripunithura, Pin – 682 301.

SCHEDULE**STATE : KERALA****DISTRICT : THRISSUR****TALUK : THRISSUR**

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

**MARATHAKKARA
BLOCK NO. 72**

108/5	0	01	40
108/20	0	00	60

STATE : KERALA**DISTRICT : ERNAKULAM****TALUK : ALUVA**

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

THEKKUMBHAGAM**BLOCK NO. 30**

239/5	0	01	00
-------	---	----	----

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1874.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडू राज्य के सेलम को केरल राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए, एक पाइपलाइन कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिये उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री बशीरकुंजु ए, सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइप लाइन प्राइवेट लिमिटेड, करुण एंक्लेव, द्वितीय तल, डोर नं. बी- 2, एस एन जंक्शन, रिफाइनरी रोड, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के सामने, त्रिपुनिथुरा, जिला ऐरनाकुलम, केरल – 682301 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

राज्य: केरल		जिला: ऐरनाकुलम		तालुक: कुन्नाथुनाडू	
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)			प्रति वर्गमीटर
		हेक्टेयर	एरिया		
कुन्नाथुनाडू (खंड सं. 36)	16 / 3	0	05	00	
	16 / 4	0	08	75	
	17 / 2	0	03	00	
	17 / 3	0	08	40	
	17 / 4	0	07	20	
	18 / 1	0	01	70	
	18 / 6	0	04	50	
	22 / 1	0	03	70	
	22 / 2	0	03	90	

राज्य: केरल		जिला: ऐरनाकुल		तालुक: आलुवा	
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)			प्रति वर्गमीटर
		हेक्टेयर	एरिया		
अंगमाली (खण्ड सं. 12)	110 / 6	0	01	00	
मूक्कन्नूर (खण्ड सं. 15)	21 / 5	0	00	41	

राज्य: केरल		जिला: त्रिशूर		तालुक: चालक्कुडी	
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)			प्रति वर्गमीटर
		हेक्टेयर	एरिया		
काल्लूर तेक्कुमुर्ली	311 / 6	0	09	50	

राज्य: केरल		जिला: त्रिशूर		तालुक: मुकुंदपुरम	
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)			प्रति वर्गमीटर
		हेक्टेयर	एरिया		
पारापूक्कारा	874 / 1	0	03	00	
	877 / 1	0	06	90	

राज्य: केरल		जिला: पालाकाड		तालुक: पालाकाड	
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)			प्रति वर्गमीटर
		हेक्टेयर	एरिया		
कन्नाडी II (खंड सं 50)	487 / 18	0	01		04
पुथुस्सेरी मध्य (खंड सं 34)	560 / 2 पीटी	0	09		22
	560 / 3 पीटी	0	00		81

[फा. सं. आर-12031 / (196) / 2017-ओआर-I/ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. No. 1874.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/S Kochi – Salem pipeline Private Ltd;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule annexed to this notification;

Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to Sri. Basheerkunju. A, Competent Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd, Karun Enclave 2nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road, Tripunithura, Pin – 682 301.

SCHEDULE**STATE : KERALA****DISTRICT : ERNAKULAM****TALUK : KUNNATHUNADU**

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS
KUNNATHUNADU				
BLOCK NO. 36	16/3	0	05	00
	16/4	0	08	75
	17/2	0	03	00
	17/3	0	08	40
	17/4	0	07	20
	18/1	0	01	70
	18/6	0	04	50
	22/1	0	03	70
	22/2	0	03	90

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1875.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 3/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Oriental Insurance Company Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 14.10.2019.

[No. L-17011/1/2011-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI****PRESENT :** M. V. Deshpande, Presiding Officer**REFERENCE NO.CGIT-2/3 of 2012****EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF
M/S. ORIENTAL ASSURANCE COMPANY LTD.**

The Regional Manager
M/s. Oriental Insurance Company Ltd.,
Mumbai Regional Office No.2,
Oriental House, 7th Floor, 7, Jamshedji
Tata Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

AND**THEIR WORKMEN**

The Joint Secretary,
General Insurance Employees' Union,
Sterling Cinema Building,
3rd Floor, 65, Murzban Road,
Fort, Mumbai – 400 001.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER : Mr. Manoj M. Gujar, Advocate
FOR THE WORKMEN : Mr. J.H. Sawant, Advocate

Mumbai, dated the 12th September, 2019**AWARD PART-I I**

1. This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi vide its order No. L-17011/1/2011 – IR (M) dated 18.01.2012. The terms of reference given in the schedule are as follows :

“Whether the action of management of Oriental Insurance Company Ltd., Mumbai in imposing the penalty of reduction of pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses amounting to Rs.12,800/- on Shri P.J. Rakshe, Record Clerk is legal, just and proper ? What relief the workman concerned is entitled to ?”

2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices. They appeared through their respective representatives.

3. The concerned workman has filed statement of claim Ex.7. According to the second party workman he is a permanent of first party management. He has been appointed by the first party management w.e.f. 10.6.1987. He has been working in the promotional post of Record Clerk. He was informed by letter dated 28.4.2006 that the departmental enquiry would be held against him under Rule 25 of General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975. He was served with the charge sheet for alleged misconduct that while he was posted and functioning as Record Clerk in the Division office, Dadar during the year 2001, he committed misconduct to the effect that he with malafide intention

went to Division office of Ghatkopar on 10.10.2001 to get the policy No. 31/2001/01905 expired on 16.7.2001 belonging to Shri Daulat S. Narwade, renewed, he unauthorisedly put the date stamp on the date and stamp on the above office policy docket with date showing 9.10.2001 and put remarks "Please correct period and date" in order to bring the accidental vehicle within purview of Insurance Policy No. 31/2002/03886 and thereby exposed the first party to bear unwarranted T.P. liability vide MACT Case No. 2731/2001 arisen out of accident of vehicle No. MH-3-F 673 on 9.10.2001 causing injury to a third party and thus by his above act failed to maintain absolute integrity, devotion to duty, exhibited the conduct unbecoming of a public servant and acted in a manner prejudicial to the interest of the company, thereby violated Rule 3 (1) (i) (ii) (iii) Rule 4 (1), (5) of General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975.

4. According to the concerned workman, he had denied the charges leveled against him by his letter dated 9.6.2006. However, the enquiry proceedings were held on 10.7.2008 and 31.7.2008 before the Enquiry officer Smt. Sunita Ingle, Assistant Manager of the First party and thereafter the first party without considering the submission made by him vide his letter dated 3.11.09 imposed punishment of reducing his two increments.

5. According to the concerned workman, the Enquiry Officer conducted the enquiry and submitted his report in haste and without considering all the facts on record. The principles of natural justice were not followed while conducting the enquiry. As such the enquiry is bad in law and is liable to be set aside.

6. It is also the contention of the concerned workman that the charge sheet has been issued under General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975 which have no force of law. The first party is governed by the Industrial Employment (Standing) Orders Act, 1946 and the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946. There are no certified orders for the establishment of the first party. Similarly, the establishment of the first party is not exempted by the Central Government from the Industrial Employment (Standing) Orders Act, 1946. Therefore Model Standing Orders (Central) as prescribed in Schedule I to the Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 have no application. Since the charge sheet has not been issued nor the disciplinary proceedings have been initiated and conducted in accordance with Model Standing Orders (Central) Schedule I, the disciplinary action taken against him is liable to be quashed.

7. It is also the contention of the concerned workman that Mr. J.H. Kasar and W.G. Mhatre were present in the enquiry held on 1.9.09 as charge sheeted employees and Mr. Jai Kumar and Mr. Bipin Navsariwala were present in the said enquiry as Defence Assistant. Presenting Officer put leading questions to Mr. Ajay R. Pote, Vigilance officer of the first party. Such action of the Enquiry officer to put the leading questions to the witnesses is against the principles of natural justice.

8. It is then contended that the hand writing expert was not examined during in the enquiry proceedings and no second opinion from the hand writing expert approved by the government was obtained by the Enquiry officer who relied upon the hand writing expert opinion and no opportunity was given to him to examine the hand writing expert. As such the findings of the Enquiry officer are perverse. The punishment imposed of reduction of pay by two stages and recovery of legal fees and other expenses amounting to Rs.12,800/- on the second party is illegal, unjust and improper. He is therefore asking for giving directions to the first party to make the payment of wages and other benefits to him without any reduction of pay and without any recovery of his wages as if no such punishment has been imposed upon him. He is also asking for directions to the first party to make the payment of arrears with interest @ 10% retrospectively.

9. The first party management resisted the claim by filing written statement Ex.14. It is contended that the second party workman was employed with the first party as Record Clerk at their Dadar Division office during the relevant period. He during working hours without any intimation and / or permission of his superiors had gone to Division office of the first party situated at Ghatkopar on 10.10.2001. The second party workman made the endorsement on expired policy No. 31/2001/1905 in the arbitrary manner with a view to renew policy in favour of Shri D.S. Narwade. The concerned workman unauthorisedly put the date stamp on the policy docket with the date showing 09.01.2001 and put remarks "Please correct period and date" in order to bring the accidental vehicle of Mr. D.S. Narwade within the purview of the expired Insurance Policy and thereby exposed the first party to bear unwarranted Third Party liability and release the amount. The said action of the second party incurred the first party with financial losses as such the second party acted dishonestly with first party company. Accordingly, he was charge-sheeted. Charge sheet was issued on 28.4.2006. He received the charge sheet and replied the same vide his letter dt. 9.6.2006. The management of the first party decided to institute disciplinary action against the second party. Accordingly, domestic enquiry was initiated and conducted by the first party into the charges leveled against him as provided under General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975.

7. It is the case of the first party management that Mr. S.K. Basu was appointed as Enquiry Officer who conducted the enquiry in an impartial manner from 29.7.2009 to 1.9.2009 and full opportunity to defend the case was given to the second party by the Enquiry Officer. The second party participated in the said proceedings and fully defended himself. As such the enquiry held against the second party is fair, proper and legal.

8. It is also the case of the first party management that Enquiry Officer submitted his report and findings dt. 21.10.2009 to the management and has held that the charges leveled against the second party are duly proved and second party is guilty of charges. Copy of the same was given to the second party. Entire due process of law was completed. The report of the Enquiry Officer is based on evidence. Copy of the enquiry report was given to the second party and he has replied the same vide his letter dt. 3.11.2009. As such the first party complied with the entire process of law before awarding punishment to the second party. Accordingly, after considering the entire records and findings of the Enquiry Officer as well as the past service record of the second party, the first party passed order dt. 27.1.2010 and 8.2.2010 against the second party and punished him by imposing penalty of reduction of pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses amounting to Rs.12,800/-.

9. It is thus the case of the first party management that the enquiry held against the concerned workman was fair and proper and the findings of the Enquiry officer are based on evidence. First party management thus sought dismissal of the reference.

10. This tribunal has passed Award Part – I on 30.10.2017 holding thereby that the Enquiry is fair and proper and the Findings of the Inquiry Officer are not perverse. Parties are directed to argue / lead evidence on the point of quantum of punishment.

11. Thereafter parties have adduced the evidence. I heard the arguments of both the parties. In view of their submissions, I reproduce the following issues at Ex.9 along with my findings thereon for the reasons stated below :

Sr. No.	Issues	Findings
3.	Whether the punishment of reducing pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses Rs.12,800/- is shockingly disproportionate ?	No
4.	What relief the workman is entitled to ?	No
5.	What order ?	As per final order

Reasons

ISSUE NO. 3:-

12. The concerned workman has filed affidavit Ex. 43 reiterating that enquiry was not fair & proper. However, in his cross examination he has admitted that he raised his grievance before the Enquiry Officer in respect of which he has stated in his affidavit and EO has given his report on the basis of evidence on record. He thus admits that the findings of the EO are based on evidence.

13. Even then the Learned Counsel for the concerned workman submitted that the EO closed the proceedings without giving opportunity to the second party to lead evidence and as such the principles of natural justice have been violated. Submission of Learned Counsel for the concerned workman is that it is necessary to have reconsideration of Part – I award passed by this tribunal but then the fact remains that the concerned workman in his cross examination has clearly admitted that he has not challenged the Part – I award before the Hon'ble H.C. by filing writ petition. As such there is no question of reconsideration or re-appreciation of the evidence or reconsideration of Part – I award. The question therefore that comes for consideration is whether the punishment of reducing pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses Rs.12,800/- is shockingly disproportionate.

14. The second party workman was awarded the punishment of reducing his pay scale by two stages in his time scale of pay and recovery in the legal fees and the expenses incurred by the first party. He was charged on the allegations that he has done the changes in policy period by putting remark “please change date & time” on the previous year policy copy when he got to know that new policy bearing No. 2002/3886 is renewed from 10.10.2001 to 9.10.2002. It appears that hand writing expert's opinion was considered as a piece of evidence to confirm his findings by the EO to come to the conclusion that the misconduct of the concerned workman is proved. The punishment is awarded to second party as per rule 23 of General Insurance Rules and he is continued in employment. After the punishment period is over, he was restored again to his time scale. It appears therefore that no major penalty was awarded to him. Even as per the admission of the concerned workman he is in service and his two increments were stopped. After a period of 2 years his regular increments were given to him. Thus it can be said that minor punishment was awarded to him. In view of that it can be said that no prejudice has been caused to him and the punishment awarded was just & proper.

15. In view of this, the Learned Counsel for the first party submitted that the Labour Court cannot substitute the penalty imposed by the employer when the labour court found the charges to have been clearly established. In the context reliance is placed on the decision in case of Janatha Bazar South Kanara Central Co-op. Wholesale Stores and Ors. V/s. Secretary, Sahakari Naukarara Sangh & Ors. – 2007 – SCC – 517.

16. The question therefore is whether the punishment imposed upon the concerned workman is shockingly excessive or dis-proportionate to the gravity of proved misconduct. For, it is explicit that the jurisdiction of the Labour court u/s. 11 (a) of I.D. Act is not unlimited. As such section 11 (a) does not confer arbitrary power on the Industrial Court or Labour Court. The jurisdiction is supervisory in nature to be exercised where the finding of disciplinary enquiry is not based on evidence. Where there has been transgression of principles of natural justice and where the finding is perverse in the sense that no reasonable body of the persons would have arrived at such a findings, then jurisdiction u/s. 11 (a) of I.D. Act can be exercised.

17. Considering all these facts and the legal position cited above, I find that punishment imposed upon the concerned workman of reducing pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses Rs.12,800/- is not shockingly disproportionate. Punishment imposed upon him is adequate to the misconduct. Punishment imposed is minor punishment. It is not causing prejudice to him. Issue No. 3 is therefore answered accordingly as indicated against it.

ISSUE NO. 4 & 5:-

18. In view of my findings to issue No. 3 and Part – I Award, the workman is not entitled to any relief, so the reference is liable to be rejected with no order as to costs. Hence order.

ORDER

Reference is rejected with no order as to costs.

Date: 12.09.2019

M.V. DESHPANDE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1876.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 29/2018) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 15.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. जेड-16025/4/2019-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1876.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 29/2018) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. New India Assurance Co. Limited and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. Z-16025/4/2019-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT CHENNAI****ID No. 29/2018****Present:** DIPTI MOHAPATRA, LL.M., PRESIDING OFFICER

Date: 28.08.2018

Sri A. Jawaran
S/o Aruvaiah
Kerban Village
Nihunk Post
Kotagiri-643217

: 1st Party/Petitioner**AND**

The Regional Manager
M/s New India Assurance Co. Ltd.
Obli Towers, R.S. Puram
Coimbatore-02.

: 2nd Party/Respondent**Appearance:**For the 1st Party/Petitioner : Advocates, M/s. S. SaravananFor the 2nd Party/Respondent : Advocate, Sri A. S. Gunasekaran**AWARD**

This is an Application under 2A(2) of the Industrial Dispute Act filed by one Mr. A. Jawaran. The Applicant case in brief is that he was employed under the Respondent and joined on 13.05.1985 as a Record Clerk in Micro Office, Kotagiri. On a false charge, the Applicant/Petitioner was dismissed from his service on 26.10.2015. By that time his last drawn salary was Rs. 19,000/- per month. He was a permanent employee and discharging his duties to the full satisfaction of the Respondent. Being aggrieved with the order of dismissal the Applicant raised the dispute before the Conciliation Officer-The Regional Labour Commissioner. Since the matter could not be resolved, on expiry of 45 days the Applicant challenged the order of dismissal before the Tribunal seeking his reinstatement with full backwages.

2. In view of the facts of discussion held supra, perused the documents on record including the Office Note, it reveals that the Applicant raised the dispute before the Regional Labour Commissioner and after expiry of 45 days approached this Tribunal. The Learned Counsel for the Respondent strenuously raises objection on the point of Admission on Maintainability. On perusal of the Office Note it further reveals that even though after expiry of 45 days after raising the dispute before the Regional Labour Commissioner, the Applicant filed this 2A Application on dated 31.10.2018, was not within the required period of limitation of 3 years from the date of his dismissal from service i.e. on 26.10.2015.

3. In order to bring the instant Application within the ambit of the amended provision under 2A Act, it is to be seen if the Applicant approaches this Forum-The Industrial Tribunal after exhausting all pre requisites of the conditions contemplated under the provision of 2A (2) of the Act Admittedly the amended insertion under 2A of the ID Act is a beneficiary legislation for the workmen, which provides a right in favour of the workmen to approach directly to the appropriate Forum under the Act to get immediate relief.

Section 2A sub clause (2) of the ID Act reads as follows :

“Notwithstanding anything contained in Section 10 any such workmen as is specified in Sub-section (1) may, make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to therein after the expiry of forty-five days from the date he has made the application to the Conciliation Officer of the appropriate Government for conciliation of the dispute, and in receipt of such application the Labour Court or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudication upon the dispute, xx xx xx xx xx xx xx xx xx Section 2A of sub clause (3) reads as follows

“The application referred to in Sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in Sub-section (1)”

4. In combined reading of both the section it needs to be seen if the Applicant has raised the dispute before the Labour Machinery and after expiry of 45 days approached the Tribunal under 2A within a period of 3 years from the alleged date of termination. It appears the Applicant raised the dispute before the Labour Machinery on expiry of 45 days, approached this Tribunal. Admittedly, the Application under 2A was filed on 31.10.2018 which is necessarily beyond the period of limitation of 3 years from the date of the alleged termination of him from job on 26.10.2015. There was delay of 5 days. On a meticulous perusal and scrutiny on the documents available on record, it is found that not a single scrap of document has been filed by the Applicant assigning any reason to consider the 5 days delay for condonation. No petition is filed to this effect.

5. In view of the discussion held in preceding paragraphs the Application filed by the Applicant deserves no merit for consideration as not maintainable under the provisions under section 2 (2A) of the Industrial Dispute Act.

The instant Application in ID 29 of 2018 stands dismissed.

(Dictated and transcribed by PA and corrected and pronounced in the open court on this day the 28th August, 2019)

DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1877.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, मुंबई के पंचाट (संदर्भ संख्या 36/2005) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 14.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/10/2004-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1877.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2005) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-2, Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 14.10.2019.

[No. L-30011/10/2004-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT: M. V. Deshpande, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/36 of 2005

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.

The Executive Director,
HPCL, Mumbai Refinery,
B. D. Patil Marg,
Mahul, MUMBAI.

**AND
THEIR WORKMEN**

The Vice President,
Hindustan Petroleum Karmchari Union,
Petroleum House, 17, Jamshedi Tata Road,
Churchgate,
MUMBAI – 400 020.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER : Mr. L. L. D'souza Representative
FOR THE WORKMEN : Mr. Jagdish Kavalekar Representative

Mumbai, dated the 16th September, 2019

AWARD

1. This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi vide its order No. L-30011/10/2004 – IR (M) dated 18.05.2004. The terms of reference given in the schedule are as follows :

“Whether the action of the management of HPCL, Mumbai Refinery, Mumbai in reducing the manpower in FR OM & S Department from 6+1 persons per shift to 5+1 per shift w.e.f. 28.10.2003 and increasing the workload of Process Technicians by forcing them to write/make entries in the Log Book, etc. and marking as ‘absent’ those employees not falling in line with the above stated alleged action of the management, without giving any notice of change as required under Section 9A of the I.D. Act 1947 and without discussing the matter with the Union as embodied in Clauses 38 read with Clause 35 of Long Term Settlement dated 18.07.2002, is legal, proper & justified ? If not, to what relief the workmen are entitled to and from which date and what other directions are necessary in the matter.”

2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3. Read pursis Ex. 35. Concerned union wants to withdraw the reference.
4. First party has no objection for withdrawing the reference.
5. In view of withdrawal of reference, the present reference is disposed of with no order as to costs. Hence Order.

ORDER

In view of withdrawal of reference, the present reference is disposed of with no order as to costs.

Date: 16.09.2019

M. V. DESHPANDE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1878.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स अरिहन्त मार्बल माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, पंचाट {संदर्भ संख्या 07/2009 आई.टी.आर. (सी)} को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 15.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/93/2008-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1878.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award {Ref. No. 07/2009 I.T.R. (C)} of the Industrial Tribunal/Labour Court, Udaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Arihant Marble Mines and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. L-29012/93/2008-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी — श्री अरुण कुमार दुबे

प्रकरण संख्या 07/2009 I.T.R.(C)

श्री दिनेश मीणा (कलासुआ) पिता श्री शंकर मीणा
निवासी गांव कागदर, माण्डवा फला, बोबला,
तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर

...प्रार्थी

विरुद्ध

श्री प्रोपाईटर/मैनेजर,
अरिहन्त मार्बल माईन्स,
मसारी की ओवरी, जिला उदयपुर

...विपक्षी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से : श्री राजेश सिंघवी, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से : श्री आर. एस. चौहान, अधिवक्ता

:: पंचाट ::

दिनांक 01 जनवरी, 2019

भारत सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक L-29012/ 93/2008-IR{M} New Delhi दिनांक 30.01.2009 के द्वारा निम्नांकित विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया —

“Whether the action of the management of
Arihant Marble Mines, in removing
Shri Dinesh Meena (Kalasua) w.e.f. 18/7/2006
just and legal? What relief the workmen
is entitled to and from which date?”

उक्त आशय का प्रसंग प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रार्थी की ओर से दिनांक 08.02.2010 को क्लेम किया गया था तथा विपक्षी की ओर से दिनांक 01.02.2011 को जबाब पेश किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि—प्रार्थी को विपक्षी ने दिनांक 01.04.1996 को क्रेन ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया जहां प्रार्थी ने दिनांक 17.07.2006 तक लगातार कार्य किया तथा इस दौरान प्रार्थी से सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक कार्य लिया गया लेकिन उसे कोई ओवर टाईम राशि का भुगतान नहीं किया न किसी प्रकार साप्ताहिक या राष्ट्रीय अवकाश दिया गया। प्रार्थी दिनांक 18.07.2006 को प्रातः 7 बजे ड्यूटी पर पहुंचा तो उस समय विपक्षी संस्थान के मालिक एवं मैनेजर ने मौखिक आदेश से अनुचित रूप से सेवा पृथक् कर दिया। प्रार्थी को सेवा पृथक् करने से पूर्व कोई नोटिस या नोटिस—पे नहीं दी, न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। प्रार्थी ने अपने सम्पूर्ण नियोजन काल में 240 दिन से अधिक कार्य दिवस पर उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दी है। इस प्रकार सेवा पृथक् किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। इसलिए

दिनांक 18.07.2006 को की गई सेवा मुक्ति को अनुचित एवं अवैध घोषित किये जाने व समस्त लाभ सहित पुनः सेवा में बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

विपक्षी ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह अंकित किया है कि प्रार्थी को विपक्षी संस्थान द्वारा दिनांक 01.04.1996 या अन्य किसी भी दिनांक को क्रेन ऑपरेटर के पद पद नियुक्त नहीं किया तथा न ही प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में दिनांक 17.06.2006 तक लगातार कार्य किया। विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी से कभी भी सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक कार्य नहीं लिया गया। वस्तुतः प्रार्थी कभी भी विपक्षी संस्थान में नियोजन में ही नहीं रहा तो प्रार्थी से ओवरटाईम कार्य लिया जाना या साप्ताहिक या राष्ट्रीय अवकाश आदि दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी को दिनांक 18.07.2006 को सेवा पृथक नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थी कभी भी विपक्षी संस्थान की सेवा में नहीं रहा, इस कारण प्रार्थी को नोटिस या मुआवजा आदि अदा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी को साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, लेकिन प्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई, इसलिये दिनांक 05.12.17 को साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई। विपक्षी को भी साक्ष्य हेतु अवसर दिये गये, लेकिन विपक्षी की ओर से भी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई, इसलिये दिनांक 04.12.18 को साक्ष्य विपक्षी बन्द की गई।

उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से अपने क्लेम के समर्थन में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई।

प्रार्थी की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश न होने से यह साबित नहीं होता है कि प्रार्थी को कब, किस प्रकार व किस पद पर विपक्षी संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया था। साक्ष्य के अभाव में यह भी साबित नहीं होता है कि प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया। प्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश न होने से यह भी साबित नहीं होता है कि विपक्षी संस्थान के किस कर्मचारी/अधिकारी ने किस दिनांक को व किस प्रकार से सेवा पृथक किया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी दिनेश मीणा को दिनांक 18.07.2006 को सेवा पृथक किया जाना साबित नहीं होता है। इसलिये प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रसंग दिनांक 30/01/2009 को उत्तरित करते हुए पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि —

प्रबन्धक, अरिहन्त मार्बल माईन्स द्वारा प्रार्थी दिनेश मीणा (कलासुआ) को दिनांक 18.07.2006 को सेवा पृथक किया जाना साबित नहीं है।

अतः प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

पंचाट प्रकाशनार्थ समुचित सरकार को भेजा जावे।

पंचाट आज दिनांक 01 जनवरी, 2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अरुण कुमार दुबे, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1879.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, पंचाट {संदर्भ संख्या 04/2017 आई.टी.आर. (सी)} को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 15.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/22/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1879.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award {Ref. No. 04/2017 I.T.R. (C)} of the Industrial Tribunal/Labour Court, Udaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Life Insurance Corporation of India and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. L-17012/22/2016-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी — श्री अरुण कुमार दुबे

प्रकरण संख्या 04 / 2017 I.T.R.(C)

श्री भगवानलाल पिता बेलजी प्रजापत
निवासी ग्राम पुनाली,
तहसील व जिला डूंगरपुर

...प्रार्थी

विरुद्ध

श्री शाखा प्रबन्धक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
डूंगरपुर — 314 001

...विपक्षी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से : श्री राजेश खन्ना, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से : सुश्री बीना माथुर, अधिवक्ता

:: पंचाट ::

दिनांक 05 फरवरी, 2019

भारत सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक L-17012/ 22/2016-IR{M} New Delhi दिनांक 06.03.2017 के द्वारा निम्नांकित विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया —

“Whether the action of Management of Branch Manager, Life Insurance Corporation of India Dungarpur(Raj.) in terminating the service of Shri Bhagwan Lal Prajapat S/o Belji Prajapat, Village Punali, Tehsil and Distt. Dungarpur (Raj.) w.e.f. 01.02.2012 is legal and justified? If no, then to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”

उक्त आशय का प्रसंग प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रार्थी की ओर से क्लेम व विपक्षी की ओर से जबाब पेश किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि—प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षी के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 18.11.2010 को हुई थी। विपक्षी द्वारा दिनांक 29.10.2010 को प्रार्थी का अस्थायी चपरासी के पद पर साक्षात्कार लिया वह 85 दिवस हेतु डूंगरपुर व सागवाडा शाखाओं के लिये लिया गया था, परन्तु प्रार्थी से डूंगरपुर शाखा में ही कार्य करवाया गया। प्रार्थी को दिनांक 18.11.10 से 10.02.11 तक पूरा वेतन 9217/—रुपये व तत्पश्चात् 11.02.11 से 31.01.12 तक 100/—रुपये, तत्पश्चात् 135/—रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थी से शाखा में

पत्रावलिआं निकालना—रखना, कम्प्यूटर में एन्ट्रीया करना, बैंक में पैसा जमा कराना व अधिकारियों की जल सेवा करना आदि कार्य करवाये जाते थे । विपक्षी द्वारा प्रार्थी की सेवाएं मौखिक आदेश के द्वारा दिनांक 01.02.2012 को समाप्त कर दी गई । प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2010 से 31.01.2012 तक करीब डेढ़ वर्ष तक बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं दी । विपक्षी द्वारा प्रार्थी को प्रत्येक माह में 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 5 दिन आदि दिनों के हिसाब से वेतन बाउचर के जरिये भुगतान किया गया । विपक्षी द्वारा प्रार्थी की हाजरी, हाजरी रजिस्टर व मस्टररोल में ली जाती थी । विपक्षी ने प्रार्थी को सेवा पृथक् करने से पूर्व कोई कारण नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया और मौखिक आदेश से प्रार्थी की सेवा समाप्त कर दी । प्रार्थी ने एक वर्ष में 240 दिन से अधिक व केन्द्रीय कार्यालय में 90 दिन व 120 दिन से अधिक तक लगातार कार्य किया । इस बाबत प्रार्थी ने विपक्षी को दिनांक 18.05.2012 को एक नोटिस भी भिजवाया, लेकिन विपक्षी ने उसका कोई जबाब नहीं दिया । इसलिये दिनांक 01.02.2012 को की गई सेवा समाप्ति को अवैध घोषित करने व सभी लाभ पुनः नियुक्त कराये जाने की प्रार्थना की ।

विपक्षी ने अपने जबाब में यह प्रकट किया कि प्रार्थी की नियुक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम स्टॉफ रेग्यूलेशन 1960 (संशोधित 1971) के रेग्यूलेशन 8 के तहत पूर्णतः अस्थायी रूप से 85 दिन के लिये गई थी जिसके तहत प्रार्थी को सेवा में समाहित किये जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है । केन्द्र सरकार द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (संशोधित 1981) के तहत अस्थायी नियुक्ति के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । प्रार्थी ने मात्र 85 दिन दिनांक 18.11.2010 से 10.02.2011 तक कार्य किया था । विपक्षी बीमा कम्पनी ने यह भी प्रकट किया कि स्वयं प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2010 को घोषणा पत्र पर इस संदर्भ में हस्ताक्षर कर विपक्षी को दिया था कि — “अस्थायी चपरासी पद पर कार्य करने के पश्चात् स्थायी पद हेतु वाद प्रस्तुत नहीं करेगा।” प्रार्थी को अस्थायी चपरासी के पद पर दिनांक 18.11.2010 से 10.02.2011 तक के लिये नियुक्ति दी गई थी तथा दिनांक 11.02.2011 के पश्चात् प्रार्थी को न तो नियुक्ति पत्र दिया गया, न ही उसकी सेवा आगे बढ़ाने का कोई आदेश दिया गया । आकस्मिक कार्य के लिये तथा Miscellaneous Expenses के पेटे जारी किये गये बाउचरों से प्रार्थी के द्वारा विपक्षी कार्यालय में किये गये निरन्तर चपरासी के कार्य की पूर्ति नहीं होती है । प्रार्थी ने अस्थायी चपरासी के पद पर नियमों के तहत कार्य किया है, जिससे प्रार्थी को विपक्षी निगम की सेवा में स्थायी नियुक्ति पाने का अधिकार पैदा नहीं हुये हैं । दिनांक 10.02.2011 को प्रार्थी की अस्थायी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो गयी थी अतः दिनांक 31.01.2012 तक प्रार्थी निगम के कार्यालय में नियुक्त ही नहीं था तो मौखिक रूप से दिनांक 01.02.2012 को सेवाएं समाप्त कर देने का कोई मामला नहीं था । प्रार्थी की कोई हाजरी, हाजरी रजिस्टर या मस्टररोल पर नहीं ली गई थी । बिना आदेश के प्रार्थी द्वारा 240 दिन से अधिक काम किया जाना संभव नहीं है । अपने विशेष कथन में भी यह अंकित किया है कि प्रार्थी के मामले में धारा 25 (F) औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (संशोधित 1981) तथा चेयरमेन द्वारा जारी भारतीय जीवन बीमा निगम स्टॉफ रेग्यूलेशन 1960 (संशोधित 1971) के तहत चेयरमेन द्वारा जारी LIC of India Employment of Temporary Staff Instruction 1993 केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का दर्जा रखते हैं तथा इस मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इसलिये प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ।

प्रार्थी ने अपने क्लेम के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे विपक्षी अधिवक्ता ने जिरह की एवं विपक्षी की और से रवि कुमार नेगी व मेघराज कोठारी के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए जिनसे प्रार्थी अधिवक्ता ने जिरह की । दोनों पक्षों की और से संबंधित दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया ।

उभय पक्षकारान की मौखिक बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी ने विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम के यहां अस्थायी चपरासी के पद पर 85 दिनों के लिये नियमानुसार साक्षात्कार देने के पश्चात् 18.11.2010 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था तथा दिनांक 10.02.2011 तक 85 दिनों तक उसे पूरा वेतन 9217/—रुपये भत्ते सहित प्रदान किया था । उसके पश्चात् प्रार्थी ने विपक्षी के यहां दिनांक 11.02.11 से 31.01.12 तक 100/—रुपये प्रति दिन तथा उसके पश्चात् 135/—रुपये प्रति दिन की दर से मजदूरी प्राप्त कर अपना काम किया था । विपक्षी के यहां प्रार्थी शाखा में विपक्षी के निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, विपक्षी ने प्रार्थी की सेवा दिनांक 01.02.2012 को समाप्त कर दी, न तो प्रार्थी को सेवा समाप्त करने से पूर्व कोई नोटिस दिया, न ही नोटिस के ऐवज में मुआवजा दिया तथा अवैध तरीके से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई । इसके पश्चात् प्रार्थी ने कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में एक शिकायत दिनांक 13.06.2012 को प्राधिकारी, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान, डूंगरपुर के यहां प्रस्तुत की जो दिनांक 11.02.2016 को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज हो गई । तत्पश्चात् प्रार्थी ने सलाह के अनुसार केन्द्रीय श्रम विभाग में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर इस न्यायालय में रेफरेंस सक्षम सरकार द्वारा प्राप्त हुआ । विपक्षी ने अवैध तरीके से प्रार्थी की सेवा समाप्त की । अतः उसे पुनः सेवा में बहाल किया जावे तथा उसको पिछला बकाया वेतन, भत्ते, परिलाभ मय एरियर व ब्याज के दिलाया जावे तथा स्थायी कर्मचारी मानते हुए सभी लाभ दिलाये जावे । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये —

- (1) 2005 Lab.I.C. Page 3750 (Madras)
National Small Ind. Vs. The P.O.I Add. Labour Court
- (2) AIR 2000 (S.c.) Page 3522(1)
Kannian and Another Vs. Sethurama
- (3) 2011 Lab.I.C. Page 2799 (S.C.)
Devendra Singh Vs. Municipal Council Sanaur
- (4) AIR 1993 (S.C.) Page 188
Union of India Vs. Basant Lal
- (5) 2015 Lab.I.C. Page 2012 (S.C.)
Tamil Nadu Terminal Vs. Life Insurance Corp.

उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता विपक्षी का तर्क है कि इस मामले में विपक्षी की ओर से प्रार्थी को भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC of India Employment of Temporary Staff Instruction 1993 के नियमों के तहत अस्थायी चपरासी के पद पर 85 दिनों के लिये नियुक्ति दी गई थी तथा 85 दिन समाप्त होने पर उसकी सेवा समाप्त हो गई तथा उन 85 दिनों का उसे पूर्ण वेतन प्रदान किया गया। सेवा में समाहित किये जाने अथवा निगम की सेवा में निरन्तर बने रहने का वाद करने का कोई अधिकार नहीं था। नियुक्ति के विज्ञापन व नियुक्ति की शर्तों में इन शर्तों का उल्लेख था तथा नियुक्ति के समय प्रार्थी ने इस बात की अन्डरटेकिंग दी थी कि 85 दिनों के बाद उसकी सेवा समाप्त हो जावेगी और उसे स्थायी करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अस्थायी नियुक्ति को निगम द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। दिनांक 11.02.11 के पश्चात् आवश्यकता होने पर प्रार्थी ने निगम की शाखा में स्वच्छ उपकरण एवं कार्यालयीन रख रखाव के तहत काम किया था, जिसके ऐवज में विपक्षी द्वारा शाखा स्तर पर उसे भुगतान किया गया जो बाउचरों के माध्यम से किया गया था। उक्त कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थायी आदेश के तहत शाखा स्तर पर करवाया गया था, जिसके तहत शाखा में मेज कुर्सीयो की सफाई, कांच वगैरा की सफाई इत्यादि कार्य के लिये सुबह 2 घंटे कार्य कराया था, जिस बाबत उसे भुगतान कर दिया गया था। प्रार्थी ने 11.02.2011 से 01.12.2012 तक न तो चपरासी का कार्य किया और न ही उसे विपक्षी द्वारा कोई नियुक्ति पत्र दिया गया। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी स्थायी सेवा पाने का व बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी की ओर से निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये –

- (1) AIR 2006 (S.C.) Page 1806
Sec. State of Karnataka Vs. Umadevi
- (2) Supreme Court C.A.No. 4636/2006
Regional Manager SBI Vs. Mahatma Mishra
Order dated Nov. 01, 2006

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के पश्चात् मेरा विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार से है –

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत A.W.-1 प्रार्थी भगवानलाल जिसने न्यायालय में दिये गये अपने शपथ पत्र में अपने क्लेम प्रार्थना की पुनरावर्ती करते हुए उन्हीं तथ्यों को दोहराया है तथा इसकी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विपक्षी के यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर इसकी नियुक्ति दिनांक 18.11.2010 को हुई थी तथा इसने 18.11.10 को कार्यभार ग्रहण किया था तथा इसकी नियुक्ति अस्थायी चपरासी के पद पर 85 दिवस के लिये हुई थी। इस दौरान दिनांक 18.11.10 से 10.02.11 तक इसने अपना कार्य सम्पादित किया और उसे पूरा वेतन 9217/—रुपये व भत्ते विपक्षी की ओर से अदा किया गया, आगे अपनी साक्ष्य में इसने यह प्रकट किया कि दिनांक 11.02.11 से 31.01.2012 तक इसने अपनी ड्युटी की थी और इस हेतु विपक्षी ने उसे 100/—रुपये व तत्पश्चात् 135/—रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान किया था तथा दिनांक 01.02.2012 को बगैर किसी शिकायत के, बगैर जांच किये, कोई नोटिस-छंटनी मुआवजा इत्यादि दिये बगैर विपक्षी ने प्रार्थी की सेवा समाप्त कर दी। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इस गवह की ओर से Ex W-1 से Ex W-78 तक प्रस्तुत किये हैं।

इसके विपरीत विपक्षी की ओर से साक्ष्य में रविकुमार नेगी और मेघराज कोठारी को प्रस्तुत किया गया है। रविकुमार नेगी और मेघराज कोठारी ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि विपक्षी संस्थान की शाखा डूंगरपुर में प्रार्थी को दिनांक 18.11.10 से 10.02.11 तक 85 दिवस के लिये अस्थायी चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। पद पूर्णतः अस्थायी था, 85 दिन समाप्त होते ही प्रार्थी की सेवा समाप्त हो गई उसके पश्चात् न तो प्रार्थी की सेवा अवधि आगे बढ़ायी गई और न ही उसे स्थायी किया गया, न ही आगे सेवा के लिये कोई नियुक्ति पत्र जारी किया गया। आगे अपनी साक्ष्य में यह भी बताया कि शाखा कार्यालय में साफ-सफाई के कार्य के लिये दैनिक वेतन के आधार पर कार्य कराया था और उसका भुगतान उसे बाउचरों के माध्यम से "स्वच्छ उपकरण एवं कार्यालयीन रख रखाव" मद से किया गया था। उसे भुगतान तत्कालिन शाखा प्रबन्धक स्वर्गीय कांतिलाल द्वारा बाउचरों के माध्यम से किया गया था। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विपक्षी की ओर से Ex M-1 लगायत Ex M-3 साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये।

इस प्रकार दोनों पक्षों की ओर से जो साक्ष्य आई है, उसमें यह स्वीकृत रूप से सामने आया है कि विपक्षी द्वारा Ex M-2 दिनांक 15.11.2010 के तहत प्रार्थी को डूंगरपुर स्थित अपनी शाखा में पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर अस्थायी चपरासी के पद पर 85 दिवस की नियुक्ति हेतु उसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। नियुक्ति पत्र में इन शर्तों का हवाला है कि प्रार्थी की नियुक्ति 85 दिवस के लिये पूर्ण रूप से अस्थायी पद पर अस्थायी तौर पर की जा रही है तथा उसे नियमानुसार वेतन मय दैनिक भत्ता एवं मकान किराया भत्ता देय होगा तथा मूल वेतन 6180/-रुपये पर नियुक्त किया तथा इस नियुक्ति पत्र में इस शर्त का भी उल्लेख था कि प्रार्थी की नियुक्ति निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये किसी भी प्रकार की वरियता अथवा निगम में नौकरी हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा तथा समयावधि समाप्त होने के पश्चात् नियुक्ति समाप्त हो जावेगी। इन शर्तों के सम्बन्ध में प्रार्थी ने Ex M-1 कार्यग्रहण रिपोर्ट विपक्षी के यहां प्रस्तुत की। जिसमें उसने इस तथ्य बाबत घोषणा प्रदान की कि मैं अस्थायी चपरासी पद पर कार्य करने के पश्चात् स्थायी पद हेतु वाद प्रस्तुत नहीं करूंगा।

प्रार्थी का विपक्षी संस्थान में दिनांक 18.11.2010 से 10.02.2011 तक किये गये कार्य के बाबत विपक्षी की ओर से प्रार्थी को नियुक्ति पत्र दिया गया तथा निगम के नियमानुसार वेतन भुगतान प्रदान किया जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत भुगतान बाउचर Ex W-14 से Ex W-17 है।

इस प्रकार साक्ष्य से यह पूर्ण रूपेण साबित होता है कि प्रार्थी को विपक्षी द्वारा अस्थायी चपरासी के पद पर जो नियुक्ति 85 दिवस के लिये प्रदान की गई थी इस तथ्य को प्रार्थी पूर्ण रूपेण जानता था तथा 85 दिन के बाद उक्त नियुक्ति समाप्त हो जाना भी प्रार्थी के ज्ञान में था और इस बाबत उसने लिखित सहमति भी दी थी कि सेवा समाप्त होने के बाद सेवा में स्थायी किये जाने बाबत कोई मांग विपक्षी से नहीं करेगा। इस प्रकार साक्ष्य से यह पूर्णतः साबित होता है कि प्रार्थी को विपक्षी संस्थान में दिनांक 18.11.2010 से 10.02.2011 तक 85 दिवस के लिये अस्थायी चपरासी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी।

प्रार्थी की ओर से अपनी साक्ष्य में यह भी प्रकट किया गया कि दिनांक 11.02.2011 से 31.01.2012 तक उसने विपक्षी संस्थान में चपरासी के पद पर कार्य किया तथा इस हेतु विपक्षी की ओर से उसे 100/-रुपये तत्पश्चात् 135/-रुपये दैनिक मजदूरी के आधार पर उसे भुगतान किया गया। भुगतान के सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से जारी Ex W-18 लगायत Ex W-76 प्रस्तुत किये, जिसे प्रार्थी स्वीकार करता है। इसमें Ex W-18, 19 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी को दिनांक 12.02.11 से 19.02.11 तक 8 दिवस कार्य करने का भुगतान विपक्षी की ओर से जरिये बाउचर Ex W-18 किया गया तथा Ex W-20 से लेकर Ex W-76 से यह प्रकट होता है कि इस दौरान माह में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अन्दर प्रार्थी द्वारा दैनिक किये गये कार्य के सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से प्रार्थी को भुगतान किया गया। अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से Ex W-76 भुगतान बाउचर प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी को विपक्षी की ओर से 19, 20 और 21 जनवरी, 2012 को किये गये कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 31.01.2012 को भुगतान किया गया, जबकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत Ex W-77 एवं Ex W-78 बोनस बाबत है

इस प्रकार मौखिक साक्ष्य में तो प्रार्थी दिनांक 31.01.2012 तक विपक्षी के यहां कार्य किया जाना तथा दिनांक 01.02.2012 को उसे सेवा से पृथक् किया जाना बताता है, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हुई है, उसमें प्रार्थी का अन्तिम बार दिनांक 21.01.2012 तक विपक्षी के यहां कार्य किया जाना और उस बाबत भुगतान प्राप्त किया जाना प्रकट होता है जो Ex W-76 से साबित होता है। दिनांक 22.01.2012 से 31.01.2012 के मध्य प्रार्थी ने विपक्षी के यहां कोई कार्य किया हो और विपक्षी ने उसका भुगतान किया हो, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य, भुगतान बाबत बाउचर इत्यादि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें भी विपक्षी के गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में व जिरह में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि प्रार्थी ने विपक्षी के यहां 31.01.2012 तक कार्य किया हो। इस सम्बन्ध में विपक्षी के गवाह मेघराज कोठारी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने हमारे विभाग में दिनांक 01.02.11 के पश्चात् लगातार

काम नहीं किया, बीच-बीच में वह सफाई का काम करता था और उसे उसका भुगतान कर दिया गया। अतः प्रार्थी इस मामले में यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उसने विपक्षी के यहां दिनांक 31.01.2012 तक दैनिक मजदूरी के आधार पर अस्थायी चपरासी के रूप में कार्य किया तथा दिनांक 01.02.2012 को विपक्षी ने उसे मौखिक आदेश से सेवा से पृथक किया।

इस प्रकार इस मामले में जो साक्ष्य आई है उससे प्रार्थी का विपक्षी संस्थान में चपरासी के पद पर कार्य करने की प्राप्ति के बावत जो साक्ष्य आई है उससे यह साबित होता है कि प्रार्थी विपक्षी संस्थान जो केन्द्रीय निगम के अन्तर्गत आता है, उसकी ओर से जारी स्थायी आदेश के तहत Cir. No. 2Z/792/ASP/93 दिनांक 28 जून, 93 को पारित किया गया, उक्त नियमों के तहत दूंगरपुर शाखा में अस्थायी चपरासी के पद पर 85 दिवस की नियुक्ति हुई। प्रार्थी को साक्षात्कार लेने के पश्चात् नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय प्रार्थी को इस तथ्य का पूर्णतः ज्ञान था कि जिस पद पर वह नियुक्त हो रहा है वह पूर्णतः अस्थायी है तथा उसकी नियुक्ति मात्र 85 दिन के लिये है और इस बावत विपक्षी की ओर से नियुक्ति आदेश में वर्णित वेतन व भत्ते प्रदान किये गये। 85 दिन के पश्चात् दिनांक 10.02.2011 के पश्चात् प्रार्थी की सेवा स्वतः समाप्त हो गई। तत्पश्चात् इस प्रकरण में शाखा प्रबन्धक स्व. कांतिलाल द्वारा, जिनकी मृत्यु हो जाना साक्ष्य में प्रकट किया गया है, ने भारतीय जीवन बीमा निगम में स्थायी आदेश के तहत **स्वच्छ उपकरण एवं कार्यालयीन रख रखाव** के रूप में दैनिक मजदूर के रूप में प्रार्थी से अपनी शाखा में कार्य करवाया और इस बावत प्रार्थी ने दिनांक 11.02.2011 से 21.01.2012 तक दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य किया। जिस बावत उसे भुगतान स्वरूप 100/-रुपये व तत्पश्चात् 135/-रुपये प्रति दिन की दर से Ex W-18 से Ex W-76 बाउचरों से भुगतान किया गया।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2006 (S.C.) Page 1806 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविदाकर्मी, आकस्मिक श्रमिक, दैनिक मजदूरी पर नियुक्त श्रमिक के सम्बन्ध में पेरा संख्या 34 में यह अभिनिर्धारित किया है कि—

Thus, it is clear that adherence to the rule of equality public employment is a basis feature of our Constitution and since the rule of law in the core of our Constitution, a Court would certainly be disabled from passing an order upholding a violation of Article 14 or in ordering the overlooking of the need to comply with requirements of Article 14 read with Article 16 of the Constitution therefore, consistent with the scheme for public employment, this court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rule and after a proper competition among qualified person, the same would not confer any right on the appointee. If it is a contractual appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on daily wages or casual basis the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely because a temporary employee or a casual.

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में विपक्षी के यहां किये गये कार्य के सम्बन्ध में अपनी सेवा को नियमितिकरण कराने का अधिकारी नहीं है।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015 Lab. I.C. Page 2012 (S.C.) के मामले में श्रमिकगण अस्थायी रूप से स्थायी प्रकृति के कार्य कई वर्षों से लगातार कर रहे थे, उनके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार किये जाने को सही ठहराया गया था। जबकि हस्तगत मामले में प्रार्थी स्थायी प्रकृति के कार्य के संदर्भ में दिनांक 11.02.11 के पश्चात् अपनी सेवा में नहीं रहा था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि “यह सही है कि दिनांक 11.02.11 से 31.01.12 के बीच 85 दिन के लिये अन्य व्यक्तियों से चपरासी का करवाया गया।” अर्थात् प्रार्थी दिनांक 11.02.11 के पश्चात् दैनिक मजदूरी पर शाखा में साफ सफाई का कार्य कर रहा था तथा चपरासी के पद पर अन्य व्यक्ति नियुक्त थे।

अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य पृथक होने से हस्तगत मामले में उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है।

हस्तगत प्रकरण में सक्षम सरकार द्वारा जो रेफरेन्स अधिनिर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है, उसमें दिनांक 01.02.2012 से प्रार्थी को सेवा से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में विवाद है, जबकि साक्ष्य से यह पूर्णतः साबित होता है कि प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में जब दिनांक 21.01.2012 के पश्चात् कार्य ही नहीं किया तो विपक्षी द्वारा उसे दिनांक 01.02.2012 को सेवा से पृथक किया गया हो यह तथ्य साबित नहीं हुआ है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (F) के प्रावधान प्रार्थी के मामले में लागू नहीं होते।

फलस्वरूप प्रार्थी भगवानलाल को विपक्षी द्वारा दिनांक 01.02.2012 को सेवा पृथक करना साबित नहीं है । अतः प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रसंग दिनांक 06/03/2017 को उत्तरित करते हुवे पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि—

“शाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा, डूंगरपुर, शाखा डूंगरपुर (राजस्थान) द्वारा प्रार्थी श्री भगवानलाल प्रजापत पिता बेलजी प्रजापत को दिनांक 01.02.2012 से सेवा से पृथक करना साबित नहीं है ।

इसलिये प्रार्थी कोई राहत पाने का हकदार नहीं है ।

पंचाट प्रकाशनार्थ भारत सरकार को भेजा जावे ।

पंचाट आज दिनांक 05 फरवरी, 2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अरुण कुमार दुबे, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1880.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, पंचाट {संदर्भ संख्या 02/2016 आई.टी.आर. (सी)} को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 15.10.2019 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. जेड-16025/4/2019-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1880.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award {Ref. No. 02/2016 I.T.R. (C)} of the Industrial Tribunal/Labour Court, Udaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Hindustan Zinc Limited and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. Z-16025/4/2019-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी — श्री अरुण कुमार दूबे

प्रकरण संख्या 02/2016 I.T.R.

श्री छगनलाल पिता हीरालाल चमार
निवासी क्वार्टर नं. 48/2, राजपुरा दरीबा माईन्स
तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

...प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्री ईकाई प्रधान, राजपुरा दरीबा खदान,
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा, जिला राजसमन्द
2. मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
मुख्यालय स्वरूप सागर, उदयपुर
जरिये प्रबन्ध निदेशक, सह अध्यक्ष, हिन्दुस्तान जिंक लि.

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 2 (A) औद्योगिक विवाद अधिनियम**उपस्थित :-**

प्रार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
 विपक्षीगण की ओर से : श्री भरत सरूपरिया, अधिवक्ता

:: पंचाट ::

दिनांक 04 सितम्बर, 2019

प्रार्थी छगनलाल द्वारा अपनी सेवा मुक्ति बाबत सर्वप्रथम शिकायत प्रार्थना पत्र उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अजमेर के यहां प्रस्तुत किया था, लेकिन वहां पर 45 दिन की सीमा में समझौता नहीं हो सका, इसलिये प्रार्थी द्वारा यह क्लेम पेश किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता हीरालाल विपक्षी के अधीन कार्यरत थे तथा उनकी मृत्यु होने के कारण प्रार्थी को उनके स्थान पर मजदूर के पद पर नियोजित किया गया। वर्ष 2003 में प्रार्थी को एक मिनी बस ने टक्कर मार दी जिससे उसका बायां पैर टूट गया तथा कृत्रिम पैर लगाना पड़ा। प्रार्थी की नियुक्ति 11.11.1999 को मजदूर के पद पर की गई थी तथा वर्ष 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद दिनांक 25.12.2005 से प्रशासनिक विभाग में मजदूरी-III श्रेणी प्रथम पद पर रिहैबिलेशन/पदस्थापन किया गया तथा आदेश दिनांक 27.11.2012 द्वारा प्रार्थी को हेल्पर श्रेणी-III के पद पर पदोन्नत किया गया तथा प्रार्थी की द्वितीय पदोन्नति हेल्पर श्रेणी-III से क्लर्क कम टाईपिस्ट श्रेणी IV-A से पदोन्नत कर खदान विभाग में स्थान्तरित किया गया और एक वर्ष के लिये परीक्षा काल निर्धारित किया गया। सन् 2012 में प्रार्थी मैंगजीन पर कार्य के दौरान सिढीयो से गिर गया जिससे पुनः प्रार्थी का दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई और जांच के लिये गुजरात रिसर्च एण्ड मेडिकल इन्स्टीट्यूट भेजा गया जहां विशेषज्ञों द्वारा प्रार्थी की जांच के पश्चात् 4,50,000/- रुपये पैर लगाने की अनुशंसा की गई, किन्तु विपक्षीगण ने उसे पैर लगाने हेतु नहीं भेजा, जबकि प्रचलित नियमों के तहत विपक्षी का यह दायित्व था। दिनांक 24.03.2014 को अचानक विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी को शारीरिक क्षमता की जांच का पत्र देर चिकित्सालय में भेजा गया जहां डाक्टर ने उस पर सैचिक सेवा निवृत्ति लेने का दबाव डाला और प्रार्थी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर व उनकी बात न मानने पर प्रार्थी को बिना जांच किये लौटा दिया और प्रार्थी के विरुद्ध चुपचाप अयोग्यता का प्रतिवेदन विपक्षीगण को भेजा गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं दी गई। प्रार्थी को बिना सूचना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 02 अप्रैल 2015 को प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से विद्युत (भूमिगत) विभाग में स्थानान्तरित कर दिया और दिनांक 01.04.15 के आदेश से पुनः हेल्पर-III के पद पर पदावनत कर दिया गया। प्रार्थी को अन्ततोगतवा अवैध रूप से दिनांक 28 मई, 2015 के आदेश संख्या 808 द्वारा स्थायी आदेश की धारा 15(3)(A) के अन्तर्गत वर्तमान विभाग में सक्षम नहीं होने से तुरन्त प्रभाव से सेवा पृथक कर दिया। प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 की धारा 47 के अनुसार प्रार्थी को नियोजन से निर्याग्यता के कारण नहीं हटाया जा सकता है जो उसकी सेवा शर्तों का भाग है। इस कारण भी प्रार्थी की सेवा समाप्ति अवैध है। प्रार्थी को सेवा पृथक किया गया जो छंटनी की परिभाषा में आता है तथा प्रार्थी को एक माह की अग्रिम सूचना या वेतन नहीं दिया, न उसे कोई क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई। इसलिये प्रार्थी को सभी लाभो सहित पुर्ननियुक्ति कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

विपक्षी ने अपने जबाब में यह प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी नौकरी को लेकर गम्भीर नहीं रहा है तथा समय-समय पर अनाधिकृत तौर से अनुपस्थित रहता रहा है जिस पर विपक्षी द्वारा उसे कई बार चेतावनी भी दी गई। दिनांक 13.03.2003 को प्रार्थी के सड़क दुर्घटना में उसके पैर में चोट आने के कारण प्रार्थी के इलाज में होने वाला सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया गया तथा लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण कम्पनी के अधिकृत डाक्टर द्वारा उसकी मेडिकल जांच की तो उसमें पाया कि वह शारीरिक अपंगता हो गयी है तथा मेडिकल बोर्ड ने प्रार्थी को तत्कालिन पद पर काम करने हेतु अयोग्य पाया फिर भी मानवीयता के आधार पर प्रार्थी को प्रशासनिक विभाग में मजदूर तीन श्रेणी प्रथम पर दिनांक 23.12.2005 से रिहैबिलेट/पदस्थापन किया गया, परन्तु वह कार्य करने में अयोग्य सिद्ध हुआ। इसके बाद नियोजन में रखने के लिये प्रार्थी को लाईट जाब हेतु दिनांक 01.01.2015 से हेल्पर श्रेणी-2 से क्लर्क टाईपिस्ट श्रेणी-4 में मैंगजीन क्लर्क के पद पर पदोन्नत कर एक वर्ष परीक्षा काल में रखा गया लेकिन परीक्षा काल में भी उसका व्यवहार व आचरण सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने से कम्पनी के स्थायी आदेशों के तहत उसे पुनः रिवर्ट करने का प्रावधान है। कम्पनी के अधिकृत डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को कम्पनी की सेवाओं से सेवामुक्त किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था। अतः कम्पनी के स्थायी आदेश के खण्ड-15 के तहत प्रार्थी को कम्पनी की सेवाओं से सेवामुक्त किया गया। मेडिकल अनफिट कामगार को एलटीएस 9 की शर्त अनुसार मुआवजा राशि का चैक देने हेतु प्रार्थी को बुलाया गया, जिसे प्रार्थी ने लेने से इन्कार कर दिया। मानवीय आधारों पर प्रार्थी को नियोजन में बनाये रखने की पूरी कोशिश की उसके बावजूद प्रार्थी की सेवाएं कभी सन्तोषप्रद नहीं रही। इसलिये प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये गये, लेकिन प्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। विपक्षी की ओर से श्रीमती रुहि खान शैरवानी का शपथ पत्र पेश हुआ, लेकिन प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण जिरह नहीं हो सकी।

विपक्षी अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता विपक्षी का तर्क है कि इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी सेवा के सम्बन्ध में गलत आरोप के साथ क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी जिसका सेवा के दौरान दुर्घटना में पूर्व में आई चोटों के कारण पैर टूट गया था, उसके पश्चात् भी विपक्षी संस्थान की ओर से उसे सेवा से पृथक नहीं किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी के पुनः दुर्घटनास्त होने के फलस्वरूप चोट आने के कारण उसे विपक्षी कम्पनी के स्थाई आदेशों की धारा 15(3) के तहत विधि अनुसार उसकी सेवा समाप्त की गई। जहां तक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 की धारा 47 के प्रावधान के विपरीत सेवा से पृथक किया जाना बताया है, जबकि उक्त अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि विपक्षी संस्थान एक निजी क्षेत्र का संस्थान है। इसके अलावा प्रार्थी की ओर से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(OO) के तहत स्वयं को सेवा से पृथक किया जाना छंटनी के तहत होना बताया है, जबकि प्रार्थी को सेवा से पृथक किया गया था, न कि उसकी छंटनी की गई थी तथा विपक्षी की ओर से प्रार्थी के संदर्भ में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों की पालना की गई है। प्रार्थी अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है, उसकी ओर से कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है, जबकि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह पूर्ण रूपेण साबित होता है कि प्रार्थी की शारीरिक विकलांगता और विपक्षी संस्थान में कोई कार्य न कर सकने के फलस्वरूप चिकित्सीय आधारों पर उसे कम्पनी के स्थायी आदेशों के तहत सेवा से पृथक किया गया था। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में विपक्षी संस्थान में अपने पिता की मृत्यु होने के पश्चात् दिनांक 11.11.1999 को अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर मजदूर के पद पर नियुक्त होना प्रकट किया है तथा वर्ष 2003 में मिनी बस से दुर्घटना होने के फलस्वरूप प्रार्थी का दाया पैर काटना पड़ा जिससे प्रार्थी के स्थायी अपंगता आई। तत्पश्चात् भी विपक्षी के यहां सेवारत रहना और विपक्षी ने उसके कार्य से सन्तुष्ट होकर उसे हेल्पर-ii के पद से क्लर्क कम टाईपिस्ट-4 के पद पर दिनांक 01.11.15 से पदोन्नत कर खदान विभाग में स्थानान्तरित किया जाना तथा एक वर्ष का परीक्षा काल निर्धारण किया जाना प्रकट किया। आगे अपने प्रार्थना पत्र में यह प्रकट किया कि प्रार्थी पुनः सिद्धियों से गिर गया जिसके कारण पैर में चोट आई जिसका इलाज अहमदाबाद स्थित अस्पताल में चला जहां विपक्षी की ओर से भेजा गया था जहां पैर लगवाने का खर्च 4,50,000/-रुपये बताया गया है, लेकिन विपक्षी ने उक्त खर्च वहन न कर विपक्षी ने प्रार्थी को सेवा से पृथक कर दिया, जो छंटनी की परिभाषा में आता है। प्रार्थी की छंटनी किये जाने से पूर्व न तो उसे एक माह का अग्रिम वेतन दिया एवं न ही 16 वर्ष की सेवाओं के बदले क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई। इसके अलावा विपक्षी की ओर से The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 की अवेहलना करते हुए उसे सेवा से पृथक कर दिया।

प्रार्थी की ओर से अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में लिये गये उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

इसके विपरीत विपक्षी ने अपने जबाब में प्रार्थी को दिनांक 11.11.1999 को अपने संस्थान में कार्यरत प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर प्रार्थी को मजदूर के पद पर नियुक्त होना तथा प्रारम्भ से ही प्रार्थी का आचरण अपने संस्थान में सही नहीं होना, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना तथा वर्ष 2003 में हुई दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी विकलांगता आना तथा तत्पश्चात् भी विपक्षी की ओर से उसे सेवा में रखना, पुनः प्रार्थी के चोट आने के फलस्वरूप विपक्षी संस्थान की ओर से प्रार्थी का चिकित्सीय परीक्षण कराना तथा चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का विपक्षी संस्थान में कोई कार्य करने में सक्षम न होना पाया जाने पर उसे कम्पनी के स्थायी आदेशों के तहत सेवा से पृथक किया जाना बताया है। प्रार्थी के विरुद्ध The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 लागू नहीं होना तथा प्रार्थी को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(OO) के तहत छंटनी नहीं किया जाना प्रकट किया है।

उपरोक्त जबाब के सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से साक्ष्य में श्रीमती रुहि खान शेरवानी को प्रस्तुत किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श एम-1 लगायत प्रदर्श एम-20 को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया तथा बहस के दौरान विपक्षी कम्पनी के स्थायी आदेश की प्रति तथा विपक्षी कम्पनी का निजी कम्पनी के रूप में स्थापित होने के सम्बन्ध में Wikipidia की रिपोर्ट पेश की गई है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत श्रीमती रुहि खान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी को विपक्षी संस्थान में दिनांक 11.11.1999 को अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर मजदूर पर पद पर नियुक्त किया गया तथा प्रार्थी के सड़क दुर्घटना में दिनांक 13.03.2003 को गम्भीर चोट आने के कारण उसका घुटने के उपर तक पैर काटना तथा उसके स्थायी अपंगता होना, तत्पश्चात् भी विपक्षी संस्थान की ओर से प्रार्थी को अपने नियोजन में रखना तथा लाईट जोब हेतु दिनांक 01.01.2015 से उसे हेल्पर श्रेणी-2 से क्लर्क टाईपिस्ट श्रेणी-4 में पदोन्नत किया जाना बताया। लेकिन वहां भी प्रार्थी द्वारा संतोषप्रद कार्य न करना, अनुपस्थित रहना तथा दिये गये कार्यों को करने में असमर्थ रहने के कारण प्रार्थी की मेडिकल जांच के पश्चात् विपक्षी संस्थान की ओर से मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श एम-17 व एम-21 प्राप्त होना व मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार प्रार्थी का विपक्षी संस्थान में किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ होना प्रकट किया गया है, जिसके कारण कम्पनी के स्थायी आदेश के तहत उसे विपक्षी संस्थान के आदेश क्रमांक राद/म.प्र./2015/808 दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा कम्पनी के स्थायी आदेश 15(3) के तहत सेवा से पृथक किया जाना प्रकट किया गया है।

इस प्रकार विपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी की सेवा के दौरान मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श एम-17 व एम-21 जो मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी की गयी, के अनुसार प्रार्थी को दुर्घटना में आयी चोट के दौरान पैर में स्थायी अक्षमता के फलस्वरूप वर्ष 2003 में उसे जिस युनिट में वह कार्यरत था, वहां कार्य करने से अनफिट पाया गया तत्पश्चात् विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी को अलग युनिट में हल्के कार्य हेतु स्थानान्तरित किया गया। जहां एक साल की परिवीक्षा पर उसे नियुक्त किया गया। वहां भी प्रार्थी द्वारा कार्य का सम्पादन न करने पर दिनांक 30.03.2015 को मेडीकल जांच में उसे

अन्डर ग्राउन्ड कार्य व मिल में कार्य करने के अयोग्य पाया गया । फलस्वरूप प्रार्थी को विपक्षी संस्थान की ओर से स्थायी सेवा नियम 15 के उपनियम (3) (A) के तहत सेवा से पृथक किये जाने का आदेश दिनांक 28.05.2015 को जारी किया और उसे सेवा से पृथक किया गया ।

विपक्षी संस्थान के स्थायी सेवा नियम के नियम 15(3)(A) में यह प्रावधान है कि “ऐसी मानसिक रूग्णता या इस प्रकार की शारीरिक अपंगता, जिसके कारण व अपना सामान्य नेमी कार्य पूरा न कर सकता हो।” ऐसे कर्मकार को एक माह की मजदूरी देकर नियोक्ता द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है । इस स्थायी आदेश के तहत प्रार्थी को सेवा से पृथक किया जाना इस प्रकरण में प्रमाणित होता है ।

प्रार्थी की विपक्षी संस्थान द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(OO) के तहत छंटनी नहीं की गयी बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(OO)(C) के तहत सेवा समाप्ति की गई । इस अधिनियम की धारा 2(OO)(C) में यह प्रावधान है कि —“इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान कि उसका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा है।” तो इस आधार पर उसे सेवा पृथक किया जा सकता है तथा वह छंटनी की परिभाषा में नहीं आयेगा ।

अतः साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित है कि विपक्षी संस्थान में प्रार्थी को शारीरिक अक्षमता के कारण व मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रदर्श एम-17 व एम-21 के आधार पर स्थायी सेवा नियम 15 के उपनियम (3) (A) के तहत सेवा से पृथक किया गया है, उसकी छंटनी नहीं की गयी है । अतः प्रार्थी का यह कथन कि—उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी कर अधिनियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी, माने जाने योग्य नहीं है ।

इसके अलावा प्रार्थी के क्लेम प्रार्थना पत्र में अन्य आधार पर की उसे The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 के प्रावधानों के तहत सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता, इस मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं । क्योंकि विपक्षी संस्थान एक निजी क्षेत्र का संस्थान है, यह तथ्य विपक्षी की ओर से प्रस्तुत Wikipidia से यह प्रकट होता है कि विपक्षी संस्थान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड Disinvestment of Public Sector वर्ष 1999 से 2004 के मध्य पब्लिक सेक्टर से निजी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया । The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 की धारा 2(a)(j)(k) जिसमें एम्प्लोयर की परिभाषा दी गयी है, के अनुसार नियोक्ता के तहत राज्य व उसके प्राधिकरण ही आते हैं । फलस्वरूप विपक्षी संस्थान निजी क्षेत्र का संस्थान होने से उपरोक्त अधिनियम विपक्षी पर लागू नहीं होता ।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से इस प्रकरण में आयी साक्ष्य से पूर्णरूपेण साबित होता है कि विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी को विधि अनुसार शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवा से पृथक किया गया है । अतः प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है ।

उक्त विवेचन के आधार पर पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि —

प्रार्थी छगनलाल पिता हीरालाल चमार निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द को विपक्षी संस्थान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दिनांक 28.05.2015 को विधि अनुसार सेवा पृथक किया गया है ।

अतः प्रार्थी श्रमिक छगनलाल कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है ।

पंचाट प्रकाशनार्थ समुचित सरकार को (उप मुख्य श्रम आयुक्त {केन्द्रीय} अजमेर के पत्र क्रमांक ऐजे-5(61)/2015 एएलसी दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के क्रम में) भेजा जावे ।

पंचाट आज दिनांक 04 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अरुण कुमार दुबे, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1881.—राष्ट्रपति, श्री शैलेन्द्र कुमार ठाकुर, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय सं. 2, धनबाद को दिनांक 26.08.2019 से छः माह तक की अवधि अथवा नियमित पदाधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय, कानपुर के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं ।

[सं. अ-11016/02/2019-सीएलएस-II]

सतीश चन्दर, अवर सचिव

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 1881.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur to Shri Shailendra Kumar Thakur, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad for a period of six months with effect from 26.08.2019 or till joining of a regular incumbent or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/02/2019-CLS-II]

SATISH CHANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1882.—राष्ट्रपति, श्री पुर्णेन्दु कुमार श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 05.09.2019 से छः माह तक की अवधि अथवा नियमित पदाधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय, लखनऊ के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

[सं. अ-11016/02/2019-सीएलएस-II]

सतीश चन्दर, अवर सचिव

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 1882.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow to Shri Purnendu Kumar Srivastava, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur for a period of six months with effect from 05.09.2019 or till joining of a regular incumbent or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/02/2019-CLS-II]

SATISH CHANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1883.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 75/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.10.2019 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/68/2014-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1883.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 75/2014) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. - II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Serve Haryana Gramin Bank and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12012/68/2014-IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer

ID No. 75/2014

Registered On:-02.02.2015

Sh. Amit Kumar, C/o Sh. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C,
Lawyers Chambers, District Court, Gurgaon (HR).

...Workman

Versus

1. The Sr. Manager, Serve Haryana Gramin Bank, Branch Tikri City, Gurgaon (Haryana).
2. The Chairman, Serve Haryana Gramin Bank, H.O.-Near Bajrang Bhawan, Delhi Road, Rohtak (HR)-124001.
3. The Nodal/Regional Officer, Serve Haryana Gramin Bank,
Pargati Bhawan, Sector-44, Gurgaon (HR).

...Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.09.2019

Central Government vide Notification No. L-12012/68/2014-IR(B-I) Dated 11.12.2014, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of Serve Haryana Gramin Bank (formerly known as Gurgaon Gramin Bank), Gurgaon in terminating the services of Sh. Amit Kumar S/o Shri Kiroudimal w.e.f. 05.12.2013 is valid, just and legal? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”

1. Both the parties were served with notices. The workman appeared through his counsel Sh. Arun Batra. An opportunity is given to the workman for submission of the claim statement but, in spite of the several opportunities, claimant did not file any claim petition. During the pendency of the proceeding before this Tribunal, workman did not turn up for setting aside the ex parte order dated 03.09.2015, compelling the learned counsel of the claimant Sh. Arun Batra for permission to withdraw from the case and informed that workman is not in touch with him as such, he is unable to submit claim statement in the case. Learned counsel further requested that he may be permitted to withdraw from the present case and requested that appropriate order be passed.
2. In view of the above facts and statement made by the learned counsel of the workman, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim Award’. Since there is no adjudication of claim petition or case on merits as such, it would not preclude the workman from seeking fresh reference in accordance with Law.
3. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

A. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1884.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. II, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 102/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.10.2019 प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/11/2013-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1884.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 102/2013) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-41012/11/2013– IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 102/2013

Date of Passing Award- 25th July, 2019

Between:

Shri Rajender Kumar Yadav,
S/o Late Shri Hukum Singh,
Vill. & PO Manjhol, Jabardastpur
Distt. Saharanpur (UP).

...Workman

Versus

1. Divisional Railway Manager,
Northern Railway,
Ambala Division, Ambala.
2. Senior Divisional Personnel Officer,
Northern Railway,
Ambala Division, Ambala.

...Managements

Appearances:-

Claimant in person, (A/R) For the Workman
Shri Manmohan Singh, (A/R) For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of Northern Railway, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 41012/11/2013 (IR(B-I) dated 03.06.13 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of the Northern Railway, Ambala Division in not making payment of wages and other dues and consequential benefits for the intervening period from the removal of service to the date of resumption is unjustified? If so, to what relief workman is entitled to?”

As per the claim statement filed by the workman he started working for the management on 10th October, 1978 as a cleaner and got promotion to the post of fire man in the year 1980 which was a Grade-C post. Again in the year 1986 he was promoted to Grade-B and posted as Parcel Clerk/Commercial Clerk. In the year 1989 he was transferred to JUD as Parcel Clerk and again in 1992 to Delhi and posted in the Cash witness office. Again in the same year i.e 1992 he was retransferred to JUD. During this period he received the salary only till the month of January 1993 except the salary for April 1992. During this period he was not paid the bonus for 1986-1987 nor his salary for April 1992, TA, overtime allowance, etc. were paid to him despite repeated demands made in writing. Ultimately after a domestic inquiry he was removed from service on 17.02.1993. He preferred an appeal to the departmental appellate authority who on consideration set aside the order passed in the domestic inquiry and found the order of removal from service illegal. As a consequence thereof though the claimant was reinstated in service w.e.f. 16.08.1993, his monthly salary for the

intervening period coming to a total of Rs. 24000/- approximately was not paid to him alongwith the other dues. The written complaint and all efforts made by the workman turned out futile, and ultimately, the claimant retired from service. He then raised a dispute before the Labour Commissioner where a conciliation proceeding was taken up. But for the adamant attitude of the management no effective result came out and the Appropriate Government referred the matter for adjudication as per the terms of the reference. The claimant in his claim petition has prayed that the management be directed to pay him 6 months' salary for the period between 07.02.1993 to 16.08.1993 alongwith interest @ 24% per annum and other consequential reliefs.

Being noticed the management filed WS challenging the maintainability of the proceeding. It is the stand taken by the management that the Indian Railways being a central government undertaking the dispute is maintainable before the Central Administrative Tribunal for the procedure laid u/s 14 of the Central Administrative Tribunal Act 1985. It is also contended by the management that the workman before filing the claim application had not obtained a certificate from the appropriate accounts department of railway regarding his entitlement though he has complained about nonpayment of the dues. The other stand taken by the management is that the workman retired from service w.e.f 31.01.2011 and all his retiral benefits have been finalized and settled. At that time for preparation of pension paper no dues certificate was obtained from different internal departments of the management and at no point of time the workman had raised objection citing nonpayment of some dues. The claim which is in the nature of a money claim is time barred. It has also been pleaded by the management that the claim advanced by the workman are matters of record and no record relating to the same is available since as per the circular of the department the relevant records are required to be preserved for a period of 5 years only. But the claim has been filed after a gap of 20 years from the due date. To support the stand management has filed the copies of the pension papers of the claimant including a no dues certificate attached with the same and the department manual and office memorandum relating to preservation time of office records.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES

1. Whether the action of the Northern Railways, Ambala Division in not making payment of wages and consequential benefits for the intervening period from the removal of service to the date of resumption is unjustified? If so its effect?
2. To what relief the workman is entitled to and from which date?

During the proceeding the workman testified as WW1 and proved the documents which were proved in a series of WW1/1 to WW1/12. These are all photocopies of the representations made on different dates to the authorities and hand written personal copies of the claim submitted to the authorities of the management requesting release of his unpaid salary and other dues. Before filing these documents the workman had filed an application u/s 11(3) of the ID Act requesting production of the original documents like his departmental proceeding record, transfers orders, etc. But the management by filling a written reply dated 28.07.2015 denied possession of said documents explaining that the retention period for such documents is 5 years only unless there is specific information relating to a pending litigation.

The management examined one of its Commercial Manager as MW1 who testified to say that, the claim advanced by the workman is baseless and not tenable as the same are not based upon records. On behalf of the management several documents were exhibited in a series of MW1/A to MW1/D. These documents include the internal circular of the management indicating the period of preservation of different categories of the documents the copy of the pension paper of the workman including the no dues/ clearance certificate issued by the different internal departments of the management.

At the outset of the argument the Ld. A/R representing the workman submitted that the management has intentionally withheld the relevant documents and the plea taken about the destruction of the documents is not correct. It has also been argued that heavy burden is always on the management to prove or disprove the facts alleged by the claimant as based on record as the custodian of the records. In this case the management has alleged about the removal of the workman from the service on 17.02.1993 and reinstatement on 16.08.1993. Whether or not salary was paid to the workman during that intervening period is a matter of record but the management has not taken any step for producing those records for verification of the tribunal.

At the cost of repetition be it stated here the workman had called for the documents by filing an application u/s 11(3) and the management did not produce the same on the plea that the documents have been destroyed after the prescribed period of preservation. It is true that the manual or circular filed by the management shows that the records of the unpaid wages are to be preserved for the period of 6 years. But that shall not come to the rescue of the management since the workman is not claiming about his unpaid wages during the working period but for the intervening period between termination from service and reinstatement to service. In a government department or government undertaking for individual employee a service record called service book is maintained which contains the entries in details including salary rise, salary withheld punishment inflicted for departmental proceeding and the consequence of the same etc. The

service book of the employee is a permanent document preserved in the department. In this case the management could have produced the service record to disprove the demand of the workman to say that after his reinstatement all his dues were cleared. The no dues certificate attached to the pension paper or obtained during the preparation of the pension paper normally reflects the dues cleared by the employee and not by the employer.

In the case of **Gopal Krishnaji Ketkar vs. Md. Latif and others reported in AIR 1968 SC 1413** it has been held by the Hon'ble Supreme Court that the party in possession of the best evidence which could have thrown light on the dispute is bound to produce the same and the said party cannot rely upon the abstract doctrine of "onus of proof." In this case the management being the employer had acted without diligence in producing the documents for proper adjudication of the matter. In such a situation this tribunal has no hesitation in accepting the oral statement of the workman that he was not paid the salary @ Rs. 4000/- per month from the intervening period 17.02.1993 to 16.08.1993 on account of his removal and reinstatement in service. This oral evidence of the workman finds support and corroboration from the documents filed by the workman making repeated representations and request to the authorities of the management and these documents relate to a period when there was no litigation or dispute pending between the parties. It is also made clear that during the relevant time since the transaction through bank account was not in practice it is not possible on the part of the workman to produce any document to prove his stand with regard to nonpayment of salary for the intervening period i.e. from 17/02/93 to 16/08/93.

Hence, it is concluded that the management is liable to pay the salary to the workman between the period 17.02.1993 to 16.08.1993 @ Rs. 4000/- per month alongwith the DA admissible during the said relevant period. Since the workman was left deprived of his legitimate dues it is held that the management shall pay simple interest @ 6% per annum on the said accrued amount from the date when it became due and till the final payment is made. The workman is held not entitled to any other relief as claimed. Hence, ordered.

ORDER

The reference be and the same is answered in favour of the workman on contest. The management is directed to pay the arrear salary of the workman for the period 17.02.1993 to 16.08.1993 @ Rs. 4000/- per month alongwith the DA admissible during the said relevant period. It is also directed that the management shall pay simple interest @ 6% per annum on the said accrued amount to the workman from the date when it became due and till the final payment is made. It is also directed that the management shall make the payment within 3 months from the date when the award would become enforceable failing which the above said amount shall carry interest @ 12% per annum from the date when it was due and till the final payment is made. Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act 1947.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

25th July, 2019

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1885.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 36/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12025/01/2019-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1885.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.-II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12025/01/2019- IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A. K. Singh, Presiding Officer

ID No. 36/2014

Registered on:-03.12.2014

Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Chuni Lal R/o V.P.O. Mahuwala,
Tehsil & District Fatehabad, Haryana.

...Workman

Versus

1. State Bank of India, through its Chairman-cum-Managing Director, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai-400021.

2. Branch Manager, State Bank of India, Village Bhattu Kalan,
District Fatehabad, Haryana.

...Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.09.2019

1. The workman has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947, with the averment that he was appointed as Sweeper on 02.05.2002 by respondent no.2 in the State Bank of India, Bhattu District, Fatehabad at the salary of Rs.1,500/- per month and he was performed his duties quite honestly and diligently till his termination. The services of the workman were terminated on 13.11.2009 without giving any show cause notice or retrenchment compensation or enquiry and personal hearing. Thus, the termination of the workman is illegal, arbitrary, mala fide and against the provisions of Industrial Disputes Act, 1947. The juniors to the workman retained in service and Pardeep son of Umed Bagri had been appointed in place of the workman. The workman has completed 240 days of service during the previous calendar year and performed his duties from 7.00 am to 4.00 pm. The defendant-management assured the workman for his reinstatement but later refused to reinstate, adopting unfair labour practice as his name was changed from the original name Anil Kumar son of Chunni Lal and Rajpal son of Chunni Lal in their record. Workman raised a demand notice dated 22.12.2009 before the learned Assistant Labour Commissioner but proceedings of conciliation ultimately failed and ALC submitted failure of conciliation proceeding. But appropriate concerned authority did not refer the demand of workman to appropriate labour court observing that ***"Part time workers have no right for regularization. The dispute has no merit and is not maintainable."*** The workman filed a Civil Writ Petition No.16317 before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court against the order of the appropriate-authority which was allowed to be withdrawn with the observation that counsel of the claimant does not press the writ petition in view of the amendment which has to be made in the Industrial Disputes Act, 1947. It is therefore prayed that order of termination dated 13.11.2009 be set aside and the workman be reinstated in service with full back wages and other consequential benefits along with 18% interest.

2. Defendants/management have filed its written statement, alleging therein that the Government/Ministry of Labour did not made the demand of the workman to the labour court as is alleged by the claimant himself. The workman has no right to file the reference before this Tribunal in view of Section 2-A(2) as well as Section 2-A of the ID Act hence, reference be dismissed on this ground. The workman was never employed by the respondent-bank on regular, temporary or ad hoc basis and no appointment letter was ever issued to the workman. The workman does not fall within the definition of workman under Industrial Disputes Act as he has not completed requisite 240 days of service continuously. The claim is not maintainable as there is no existed a relationship of employer and employee between the claimant and answering respondent. The Hon'ble Supreme Court has held in so many cases mentioned in Paragraph 5 of the written statement that if unauthorized appointment has been made without any sanctioned post from the concerned-authority and was a back door entry, in such circumstances, Section 25-F of the Act is not applicable. In fact, the workman was engaged as part time on daily wage basis @ Rs.50/- per day. No fixed remuneration was paid to the workman. After sweeping of the branch, he was free to go elsewhere and was not under the control and supervision of the Branch Manager. The service of the said workman was discontinued when a permanent Sweeper was posted at Bhattu Kalan Branch. There is no relation of seniority and juniority between the workman and Sh. Pradeep Kumar. It is therefore, prayed that in view of the submission made above, the workman is not entitled for reinstatement as is prayed.

3. Both the parties were given opportunities to file their evidence. Workman Naresh Kumar has filed his affidavit Ex.A-1 along with Annexure W1 to W6. He has accepted that he was kept as Sweeper by the Manager without any advertisement. He has accepted that neither any appointment letter was issued to him nor interview was conducted. This witness has accepted that he was kept as daily wagger and was paid for the days he worked through voucher. He has

denied the suggestion of the management-counsel that he did not completed 240 days in a preceding year prior to the termination of his services.

4. Management has examined Sh. Samundra Gupta Maurya, Branch Manager, State Bank of India, Bhattu Kalan, Distt. Fatehabad, who has filed his affidavit Ex.MW1 and stated on oath that he was not posted in the year 2002 at Bhattu Kalan Branch of the Bank. He has admitted that he is not in a position to tell whether the attendance register of the year 2002 pertaining to the workman is with the management or not. He has also stated that claimant was paid through voucher regarding petrol, diesel and other miscellaneous expenditure along with stationary till the appointment of Pradeep Kumar, regular employee of the bank. he has accepted that the work of Sweeping is done through outsourcing agency at present.

5. I have heard Sh. Arun Batra, Ld. Counsel for the workman and Sh. S.K. Gupta, Ld. Counsel for the management and perused the file carefully.

6. At the very outset, it can be observed that management has taken legal issue regarding the maintainability of the claim petition by virtue of its time barred in the light of the provisions contained in Section 2-A sub-Clause 3 of the Industrial Disputes Act, 1947. This specific plea has been taken by the management in Para 2 of the written statement as such, it is the legal obligation of the Tribunal to discuss the issue at first. On the basis of the plea, raised by the respondent-management, I am of the view that following points would arise for consideration:—

- (i) *“Whether Labour Court can entertain a claim petition filed under Section 2-A(2) of Industrial Disputes Act, 1947 after five years from the date of dismissal/retranchment of service otherwise terminated?”*
- (ii) *Whether Labour Court has right to condone the delay in filing claim statement though sub-Section (3) of Section 2-A barred such claim?”*
- (iii) *Whether the claimant is entitled for relief as claimed in the claim petition?*

7. So far as issue no.1 is concerned. Section 2-A of the I.D. Act enables the individual workman to raise a dispute connected with or arising out of his discharge, dismissal, retranchment or otherwise termination of his services by his employer and by legal fiction it would constitute “Industrial Dispute”. No other type of dispute regarding an individual workman is contemplated by Section 2-A. After the enactment of Section 2-A, it is not necessary that a dispute relating to the discharge, dismissal, retranchment or otherwise termination of service of a workman must be sponsored by a trade union or a substantial number of workman. In other words, even if it is not sponsored by a trade union or a substantial number of workman, such a dispute will be deemed to be an industrial dispute. Section 2-A of the ID Act reads as under:

“2-A. Dismissal, etc., of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute—

- (1) *Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of such discharge, dismissal, retranchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute.*
- (2) *Notwithstanding anything contained in Section 10, any such workman as is specified in sub-Section(1) may, make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to therein after the expiry of forty-five days from the date he has made the application to the Conciliation Officer of the appropriate Government for conciliation of the dispute, and in receipt of such application the Labour Court or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudicate upon the dispute, as if it were a dispute referred to it by the appropriate Government in accordance with the provisions of this Act and all the provisions of this Act shall apply in relation to such adjudication as they apply in relation to an industrial dispute referred to it by the appropriate Government.*
- (3) *The application referred to in sub-Section(2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retranchment or otherwise termination of service as specified in sub-Section(1).”*

A bare reading of above provision would indicate that a dispute covered under sub-Section(1) can be agitated or questioned by a workman by making an application directly to the Labour Court or Tribunal for adjudication of such dispute and such application should be filed before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retranchment or otherwise termination of service. In other words, the right conferred under Section 2A would lapse immediately preceding the date of expiry of three years of the date of dismissal, discharge etc. Sub-Section (3) of Section 2A would operate independently. The right available to the workman under Section 2A is not withstanding anything

contained in Section 10 of the ID Act. Hence, it is observed that this Tribunal has got no power to entertain claim petition filed beyond limitation as is employed in the above provisions.

ISSUE NO. 2:

8. The second question arises for consideration is whether the dispute raised after five years from the date of dismissal can be entertained by the Labour Court or Tribunal condoning the delay, if any, in raising the dispute? Learned counsel of the workman has contended that limitation should be counted from the date of the order of the Hon'ble High Court dated 11.09.2014 which is objected by the learned counsel of the management by stating the fact that there is nothing in the order of the Hon'ble High Court which permit the Tribunal to count the limitation period from 11.09.2014 as is asserted by the workman counsel. The order of the Hon'ble High Court dated 11.09.2014 runs as follows:—

“Counsel for the petitioner does not press the writ petition in view of the amendment, which has been made in Section 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 and prays for withdrawal of the same with liberty to approach the Court of competent jurisdiction.”

9. It is pertinent to mention that writ petition filed before the Hon'ble High Court has been withdrawn. In view of the amendment which has been made under Section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947. Thus, it is crystal clear that claimant has to file the claim petition in view of amended Section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947. Keeping the principles in mind, a reading of Section 2-A(2) would lead to an irresistible conclusion that time stipulated for invoking the jurisdiction of the Labour Court or the Tribunal as the case may be, has to be necessarily “before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in sub-Section (1). “Time limit for making an application to the Labour Court stipulated in sub-Section (3) of Section 2A does not appear to have a bearing to the provisions of sub-Section (2) of Section 2A. In any event right conferred under Section 2A would lapse immediately preceding the date of expiry of three years from the date of dismissal, discharge etc.,. In other words, the limitation of three years prescribed under sub-Section (3) of Section 2A being mandatory, same cannot be condoned by taking recourse to Section 5 of the Limitation Act, 1963 which has no application to the provisions of Industrial Disputes Act, 1947.

ISSUE No. 3:—

10. This issue relates with the relief claimed by the workman for reinstatement with continuity of service and other benefits available therein. Undoubtedly, learned counsel of the management has raised a contention that claimant is not a workman as defined under Section 2(S) of the Act and respondent does not come within the purview of “Industry”. But both the arguments have no force in the light of the observation made by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Devinder Singh Vs. Municipal Council, Sanaur, AIR 2011 Supreme Court 2532** and **Bangalore Water Supply & Sewerage Board Vs. A. Rajappa 1978(36) FLR 266**. Thus, I am of the considered opinion that there exist relationship of employer and employee between the workman and management and management is duty bound to terminate the services of the workman as per provisions envisaged under the Industrial Disputes Act, 1947.

11. The question relates to be same whether there is sufficient evidence to hold that workman was regularly appointed by respondent no.2 on monthly salary of Rs.1,500/- and worked 240 days on each year upto his illegal termination as alleged in the claim petition. Workman/claimant Naresh Kumar has himself admitted in his cross-examination that he was appointed as daily wager and was paid for the days he worked through vouchers. Thus, it is clear that he was not appointed on monthly basis as is alleged by him in his claim petition and was paid for the days he was employed by the management as such.

12. Though, workman has alleged in his claim petition as well as in his affidavit that he worked 240 days in each year, prior to the termination of his services by the respondent-bank but he has filed the documents along with affidavit photocopy of bill regarding purchasing of diesel, pen, electronic items, surf, phenyl etc. for which he was paid by the respondent-management but he has not filed any documents to prove that he was serving with the management from 02.05.2002 to 13.11.2009 as is alleged in his claim petition. It is pertinent to mention that he has not made any request before the Tribunal to summon any document pertaining to his attendance or monthly payments in lieu of his services rendered to the management. Hon'ble Supreme Court in its latest judgment **The Superintending Engineer TWAD Board & Another Vs. M. Natesan, etc.[Civil Appeal Nos.4875-4884 of 2019 arising out of SLP (C) Nos.21962-21971 of 2018]**, has reiterated again that initial burden lies on the workman to prove that he worked 240 days preceding year of his termination but no effort is made by the workman to prove this crucial aspect of the case which require notice or one month salary, in lieu of notice under Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Thus, having gone through the above critical analysis and evidence, this Tribunal is of the considered opinion that claim made by the workman through this is not maintainable as it is time barred as well as without any evidence regarding his illegal termination by the management. Resultantly, claim petition is liable to be dismissed and answered accordingly.

13. In view of the aforesaid discussion, I am of the considered view that Issue No.1 and 2 has to be answered in the negative namely, Labour Court cannot entertain a claim petition filed under Section 2A(2) of the I.D. Act after five

years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or termination and this Tribunal has no right to condone the delay more than five years in filing the claim petition. Even otherwise there is no explanation forthcoming for the delay in not raising the dispute from 13.11.2009 to 21.07.2010 from the date of termination till the date of filing of application before the Assistant Labour Commissioner. The contention of the workman that if there is any delay regarding the filing of claim petition it is due to the conduct of management on pretext of false promise for payment and reinstatement has no force in the eye of law.

14. Having gone through the factual and legal proposition, I am of the view that claim petition is time barred as such, this Tribunal has no jurisdiction to entertain the present claim petition and passed the order on merit without jurisdiction as such, the claimant is not entitled for any relief and the claim petition is liable to be dismissed.

15. The reference is answered accordingly. Let copy of the award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1886.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 178/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/59/2010-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1886.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 178/2011) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. - II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of Patiala and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12011/59/2010- IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer

ID No.178/2011

Registered on:-08.06.2011

Sh. Paramjit Singh S/o Late Sh. Bhag Singh, presently working as
Single Window Operator, State Bank of Patiala, Kurali.

... Workman

Versus

State Bank of Patiala through Deputy General Manager,
SCO No.99-101, Sector 8-C, Chandigarh.

...Management

AWARD

Passed on:-04.09.2019

Central Government vide Notification No. L-12011/59/2010-IR(B-I) Dated 25.05.2011, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of State Bank of Patiala in imposing the penalty of reduction of basic pay by one stage on Shri Pramjit Singh Window Operator, SBP, Kurali Branch vide their order dated 22.11.2006, is legal and justified? To what relief the workman is entitled?”

1. The facts, in brief, are that, the workman appeared and filed claim statement, alleging therein that he was employed as Single Window Operator with the respondent-bank at Kurali Branch. The workman/claimant rendered unblemished service of 26 years and has always maintained highest level of personal integrity and honesty in his conduct and dealings. The workman/claimant has also performed duties of accepting withdrawal forms and cheques from the customers and making payment to the customers in accordance with the prescribed procedure, norms and well established practices of the respondent-bank. The said procedure is invariably followed by the workman. It is not out of place to mention that banking business has to be carried out at the branch even when the staff is short due to absence of employees and various practices to copy up with the work pressures, even though, deviant from the prescribed rules have to be adopted and implemented as the business cannot be closed down on any pretext. It is not uncommon at the ranch functional model especially in the semi urban branches that the Branch Manager or any other officer of the bank could first pay the customer in a hurry and thereafter could insist for payment from the Cashier of Single Window Operator in respect of a withdrawal of cheque drawn by a customer of a bank, apparently to make good the payment already made or to deliver such payment to the customer in question. The claimant having to his credit 26 years experience in the bank bona fide states that such practice of routing the cash transaction through the other officers at the branch level is well accepted and well established practice without any taint or trapping of illegality or impropriety. Subsequently, one Malkit Singh, Head Cashier at the branch had committed fraud and various payments from the claimant stood wrongly pocketed by said Malkit Singh. Consequently, various investigations were carried out in the matter and Sh. Malkit Singh also admitted his lapse. Ultimately, disciplinary authority acting unreasonably and hastily order a departmental enquiry against the claimant and passed a punishment order dated 22.11.2006 which is marked as Annexure C-3. Aggrieved by the said order, the workman/claimant preferred an appeal to the appellate-authority dated 19.12.2006 which is marked as Annexure C-3. The appellate-authority vide its order dated 07.09.2007 rejected the appeal of the workman by a non-speaking perfunctory and mechanical order without considering the facts on record. A copy of the impugned order dated 07.09.2007 of the appellate-authority which was forwarded vide letter dated 11.09.2007 to the claimant is marked as Annexure C-5(Colly). The claimant/workman raised a demand notice dated 23.04.2010 before the Assistant Labour Commissioner which is marked as Annexure C-6 and reply to the said demand notice filed by the respondent-bank is marked as Annexure C-7. It is prayed that the claim may kindly be allowed and the impugned orders dated 07.09.2007, 11.09.2007 and 22.11.2006 be set aside and the basic pay be restored by notionally wiping out the effect of impugned orders and financial loss suffered by the claimant may kindly be compensated by payment of appropriate interest to meet the ends of justice.

2. Respondent-management filed written statement, alleging therein that the workman/claimant while working as Single Window Operator posted at Kurali has committed serious acts of misconduct for which he was served a charge-sheet dated 01.06.2006. He also alleged that the present reference deserves to be dismissed on the ground of mis-joinder and non-joinder. He has admitted that the workman was accepting the withdrawal forms, cheques and making payments to the customers. He further alleged that the workman/claimant was not performing his duties as per norms of the bank and was negligent, deviant from prescribed rules in performing his duties. It has further stated that it was proved on record that the workman had made the payment of withdrawal form to Malkit Singh, Head Cashier of the Branch instead of account-holder which resulted into a fraud which has tarnished the image of the Bank among the general public and may weed off potential customers from approaching the Bank for banking purposes. The workman/claimant has himself admitted that he had made the payment to Malkit Singh instead of account holder which is against the Bank's instructions, rules and norms as contained in Chapter B-3, Para 6.1(a&k) of the Bank's Book of Instructions. Hence, the action of the disciplinary authority in awarding the punishment and taking a lenient view in the matter is legal, just and in accordance with law and the punishment is quite commensurate with the gravity of charges leveled against him. It is therefore, prayed that the present reference may kindly be dismissed in view of the facts narrated above.

3. Both the parties were given opportunity to lead evidence.

4. Workman Paramjit Singh has filed his affidavit Ex.W1 and has been cross-examined by the management-counsel. Management examined Sh. Kewal Krishan Sharma, Assistant General Manager, who filed his affidavit Ex.R1. This witness is not examined by the workman-counsel as the workman was proceeded ex parte on 28.07.2015.

5. At the stage of arguments, workman filed an application for withdrawal of the claim along with his affidavit, stating therein that the respondent-management took a lenient view in favour of the applicant/workman in the context of his promotions in the career path of the applicant/workman and requested that the application may kindly be allowed and the reference may kindly be returned with a finding that the claim of the applicant/workman has become infructuous and the reference does not consequently survive for adjudication. Both the parties prayed that the reference be decided in the light of settlement arrived at between the parties.

6. It is now well settled position in law that any settlement arrived at between the parties is legally binding upon both the parties in terms of the provisions of Section 18 of the ID Act. In view of the amicable settlement, there is no requirement to proceed with the present reference. The application for withdrawal of the claim along with affidavit of the workman shall form the integral part of the Award.

7. Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID Act, 1947.

A. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 1887.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 114/2014, 115/2014, 116/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.10.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/06, 08, 07/2015—आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1887.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 114,115,116/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.-II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Serve Haryana Gramin Bank and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12012/06, 08, 07/2015—IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer

1. ID No.114/2014

Registered On:-02.03.2015

Sh. Hari Prem S/o Sh. Inderjeet, C/o Sh. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C, Lawyers Chambers, District Court, Gurgaon (HR).

2. ID No.115/2014

Registered On:-02.03.2015

Sh. Tamir Khan, S/o Sh. Mauj Khan, C/o Sh. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C, Lawyers Chambers, District Court, Gurgaon(HR).

3. ID No.116/2014

Registered On:-02.03.2015

Sh. Des Raj S/o Sh. Suraj Bhan, C/o Sh. Rajinder Pathak,
Chamber No. 169-C, Lawyers Chambers, District Court, Gurgaon (HR).

...Workmen

Versus

1. The Chairman, Serve Haryana Gramin Bank, H.O.-Near Bajrang Bhawan, Delhi Road, Rohtak (HR)-124001.
2. The Nodal/Regional Officer, Serve Haryana Gramin Bank, Pargati Bhawan, Sector-44, Gurgaon (HR).

3. The Sr. Manager, Serve Haryana Gramin Bank,
Branch Tikri City, Gurgaon (Haryana). ...Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.09.2019

Central Government vide Notification No. L-12012/06/2015-IR(B-I), L-12012/08/2015-IR(B-I), L-12012/07/2015-IR(B-I), Dated 30.01.2015, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the following Industrial disputes separately for each workmen related to the Department of Haryana Gramin Bank for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of Serve Haryana Gramin Bank(formerly known as Gurgaon Gramin Bank), Gurgaon in terminating the services of Sh. Hari Prem, (Sh. Tamir Khan, Sh. Desh Raj) w.e.f. 05.12.2013 is valid, just and legal? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”

1. Since the all above mentioned references are same hence, they are decided by common judgment.
2. Both the parties were served with notices. The workman appeared through his counsel Sh. Arun Batra. An opportunity is given to the workman for submission of the claim statement but, in spite of the several opportunities, claimant did not file any claim petition. During the pendency of the proceeding before this Tribunal, workman did not turn up for setting aside the ex parte order dated 03.09.2015, compelling the learned counsel of the claimant Sh. Arun Batra for permission to withdraw from the case and informed that workman is not in touch with him as such, he is unable to submit claim statement in the case. Learned counsel further requested that he may be permitted to withdraw from the present case and requested that appropriate order be passed.
3. In view of the above facts and statement made by the learned counsel of the workman, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim Award’. Since there is no adjudication of claim petition or case on merits as such, it would not preclude the workman from seeking fresh reference in accordance with Law.
4. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.
5. Copy of the award be kept in ID No.115/2014 titled as Tamir Khan Vs. Serve Haryana Gramin Bank and ID No.116/2014 titled as Des Raj Vs. Serve Haryana Gramin Bank.

A. K. SINGH, Presiding Officer